https://www.facebook.com/KamalSandeshBjp/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

भारत-इजराइल के बीच
7 अहम समझौते

वर्ष-12, अंक-15, 01-15 अगस्त, 2017 (पाक्षिक) ₹20

भारत के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद

'देश की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने में सरकार सफल हुई है'

बिहार में फिर राजग सरकार

जीएसटी सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन है

कारगिल विजय दिवस पर शहीदों की स्मृति को नमन करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

दिल्ली में विस्तृत प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का स्वागत करते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन एवं अन्य नेतागण

गुजरात में पन्ना प्रमुख सम्मेलन के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का अभिनंदन करते गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी एवं अन्य नेतागण

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 भारत के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद

राजग के उम्मीदवार और बिहार के राज्यपाल रहे श्री रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। गत 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के आए नतीजे में उन्होंने 65 फीसद से अधिक वोट हासिल कर जीत दर्ज की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी श्री अनूप मिश्र ने...

वैचारिकी

सांस्कृतिक पुनरुत्थान 19

श्रद्धांजलि

कुशाभाऊ ठाकरे 20

लेख

राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति पर चिंतन 21

क्या ममता की तृणमूल कांग्रेस तेजी से जिन्ना की मुस्लिम लीग बन रही है? 23

जीएसटी सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन है 25

अन्य

देश की सफलता का मंत्र उसकी विविधता में है: रामनाथ कोविन्द 10

राजग के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बने वेंकैया नायडू 12

भारत-इजराइल के बीच 7 अहम समझौते 27

बिहार में फिर राजग सरकार 30

विद्युत उत्पादन की लागत घटाने के लिए मेरिट एप और ई-बिडिंग पोर्टल लांच 31

'श्यामा प्रसाद मुखर्जी - हिज विजन ऑफ़ एजुकेशन' का लोकार्पण 32

तीनों देशों की संयुक्त प्रतिबद्धता का प्रदर्शन था 'मालाबार अभ्यास' 33

संगठनात्मक गतिविधियां

13 देश की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने में सरकार सफल हुई है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष...

15 'राज्य में गरीब तबकों को आगे बढ़ाने के सराहनीय प्रयास हुए'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने तीन दिवसीय...

सरकार की उपलब्धियां

16 किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार के बहुआयामी कदम

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा...

18 पटसन किसानों की आय 10,000 रुपये से अधिक बढ़ी

बेहतर कृषि आर्थिक व्यवहारों को लोकप्रिय बनाने/ प्रचलित करने के लिए वर्ष 2015 में लांच की...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

देश को लूटनेवालों के खिलाफ जब कानून अपना काम करता है, तो सियासी साजिश की बात करके बचने का रास्ता खोजने वालों के विरुद्ध एकजुट होना होगा।

@AmitShah

'कारगिल विजय दिवस' के अवसर पर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को परास्त करने वाले सभी जवानों को नमन!

@Ramlal

श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मु.मं. व श्री सुशील मोदी ने उप मु.मं.पद की शपथ ली। अब राजग की 18 राज्यों में सरकार। बधाई!

@rsprasad

डिजिटल लेन-देन में भारी वृद्धि से भारत के लोगों के बीच इसकी व्यापक व बढ़ती स्वीकृति का पता चलता है।

facebook

हम पर्यावरण के संरक्षक होने की बजाय शोषक बन गये हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियां धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं। दुनिया सभी के लिए है। हम नर्मदा को बचाने के लिए नीतियां बना रहे हैं। हमारा ऐसा सिस्टम बनाने पर ज़ोर है कि अवैध उत्खनन पूरी तरह से समाप्त हो जाये। हम नदी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऐसी माइनिंग पालिसी बनाएं ताकि रेत उपयुक्त मात्रा में और उचित दाम पर उपलब्ध हो। वर्कशॉप में बहुत उत्कृष्ट विचार आएं हैं, मुझे विश्वास है कि हम बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे।

— शिवराज सिंह चौहान

झारखण्ड में बीजेपी ने स्थिर सरकार दी। पिछले ढाई साल में स्थानीय नीति के तहत एक लाख नौकरियां दीं। 50 हजार नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। विकास दर के मामले में गुजरात के बाद झारखण्ड देश में दूसरे नंबर पर है। बिहार में भी कमल खिलाए जाने की जरुरत है। कमल समृद्धि का प्रतीक है और समृद्धि विकास का सूचक है।

—रघुबर दास

रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति

भारतीय लोकतंत्र कितना मजबूत एवं परिपक्व है इसका एक उदाहरण श्री रामनाथ कोविंद का देश का 14वां राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना है। उनका चुना जाना इस बात को रेखांकित करता है कि भारतीय लोकतंत्र में यह क्षमता है कि समाज के अत्यंत कमजोर पृष्ठभूमि का भी व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर सकता हैं। इससे भारतीय लोकतंत्र के समावेशी चरित्र का पता चलता है, जो सामाजिक परिवर्तन एवं समाज-सुधार के प्रति प्रतिबद्ध है। श्री रामनाथ कोविंद का उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव के गरीब दलित परिवार से राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा एक चमत्कार लगता है, परन्तु यह लोकतंत्र की शक्ति से ही संभव हो सकता है। जब कोई रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनता है और कोई नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री तब इस देश का गरीब से गरीब आश्वस्त महसूस करता है कि देश सही दिशा में बढ़ रहा है और हर वर्ग का सशक्तिकरण हो रहा है। इससे भाजपा के अंत्योदय एवं समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति गहरा समर्पण भी प्रमाणित होता है।

राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद वे अपने संबोधन में श्री कोविंद ने भारत की अनूठी विविधता को ही देश की शक्ति बताया। महात्मा गांधी एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए उन्होंने देश के सर्वांगीण विकास तथा समरस-समावेशी समाज के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। श्री रामनाथ कोविंद को 65 प्रतिशत मतों के साथ एक बड़े अंतर से चुना गया है। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके चुनाव पर भी कांग्रेस अपने संकीर्ण राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकी और तर्कहीन बातों पर उनकी आलोचना करने का प्रयास किया। कांग्रेस को श्री प्रणव मुखर्जी से सीख लेना चाहिए, जिन्होंने इस सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाये रखा। जिस प्रकार की विदाई उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं अन्य मंत्रियों से मिली उससे उनका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व एवं सार्वजनिक जीवन में उनके कद का पता चलता है। श्री रामनाथ कोविंद के फूस की झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा इस देश के गरीब से गरीब को यह आश्वस्त करता है कि उनका एक प्रतिनिधि उनके हितों की रक्षा तथा उनकी चिंता करने के लिए अब राष्ट्रपति भवन में भी मौजूद है।

अपनी अंतरात्मा की आवाज पर तथा बिहार की जनता के हितों के पक्ष में खड़े हाने के लिये नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में उनका स्वागत कर फिर से लूट-खसोट की राजनीति पर चोट की है।

बिहार में फिर एनडीए सरकार

बिहार में पुनः एक बार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने शपथ ले ली है। महागठबंधन सरकार में लालू यादव एवं उनके परिवार के कारनामों से सरकार की स्थिति दिनोंदिन बद से बदतर होती जा रही थी। एक ओर जहां बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच देश की विभिन्न एजेंसियां कर रही थी, वहीं दूसरी ओर विकास एवं सुशासन के पैमाने पर भी बिहार निरंतर पिछड़ रहा था। अपने विरुद्ध लगे आरोपों तथा अपने परिवार के कारनामों पर लालू यादव द्वारा कोई सफाई न देने के जिद से नीतीश कुमार के लिये असमंजस की स्थिति बन गई थी। इससे सरकार की विश्वसनीयता लगातार मिटती जा रही थी। इससे बिहार के सरकारी कामकाज पर असर पड़ रहा था और एक संकट का वातावरण बना हुआ था।

अपनी अंतरात्मा की आवाज पर तथा बिहार की जनता के हितों के पक्ष में खड़े हाने के लिये नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में उनका स्वागत कर फिर से लूट-खसोट की राजनीति पर चोट की है। बिहार पूर्व की एनडीए सरकार की उपलब्धियों को लोग याद करते हैं जब विकास एवं सुशासन के पैमाने पर बिहार ने अपनी मजबूत स्थिति दर्ज की थी। लालू यादव एवं कांग्रेस के साथ मिलकर बनी सरकार में बिहार की स्थिति बदतर होने लगी थी और फिर से प्रदेश पर जंगल राज का खतरा मंडराने लगा था। महागठबंधन से निकलकर एवं अपने निर्णायक कदम से नीतीश कुमार ने बिहार को बचा लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब बिहार पुनः विकास एवं सुशासन की राह पर मजबूती से चल पड़ेगा। कई वर्षों के बाद ऐसा होने जा रहा है कि केन्द्र और प्रदेश में एक ही गठबंधन की सरकारें हैं जो कि बिहार के लिये एक सुनहरा अवसर है। बिहार अनेक संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है और अब एनडीए सरकार के नेतृत्व में यह नई ऊंचाइयों पर उड़ान भरने को तत्पर है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

भारत के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद

राजग के उम्मीदवार और बिहार के राज्यपाल रहे श्री रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। गत 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के आए नतीजे में उन्होंने 65 फीसद से अधिक वोट हासिल कर जीत दर्ज की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी श्री अनूप मिश्र ने बताया कि कोविंद को 65.65 फीसद मत मिले, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार को 34.35 फीसद वोट मिले।

श्री कोविंद ने करीब 31 फीसद मतों के अंतर से श्रीमती मीरा कुमार को पराजित किया। 71 वर्षीय श्री कोविंद को 2930 मत प्राप्त हुए जिसका मूल्य 7,02,044 मत है। श्री कोविंद भाजपा के पहले सदस्य हैं जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। श्रीमती मीरा कुमार को 1844 मत प्राप्त हुए जिसका मूल्य 3,67,314 है।

श्री कोविंद को 522 सांसदों के वोट मिले जिसका मूल्य 369576 है, जबकि श्रीमती कुमार को 225 सांसदों के मत प्राप्त हुए जिनका मूल्य 159300 है। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में 4,896 मतदाता है जिनमें 4,120 विधायक और 776 सांसद शामिल हैं। श्री कोविंद ने श्रीमती मीरा कुमार को 3.34 लाख मतों से हराया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई देते हुए निर्वाचक मंडल में उन्हें मिले व्यापक

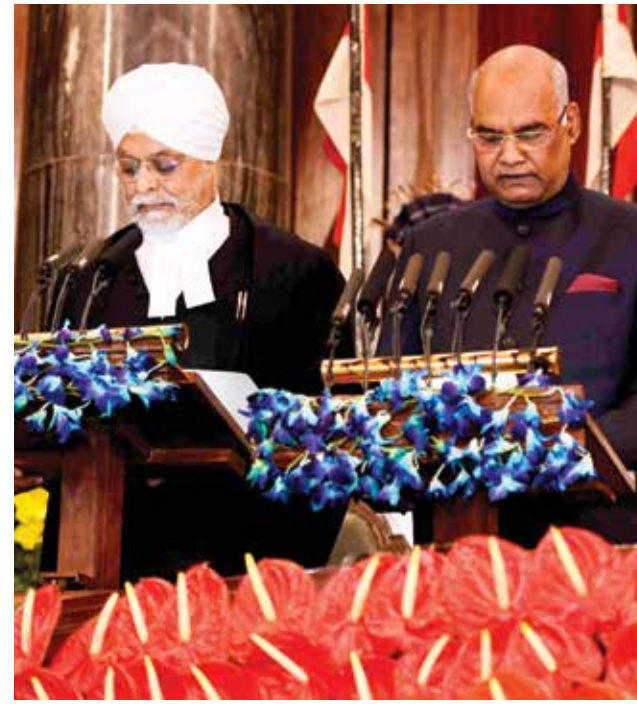

रामनाथ कोविंद ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री जगदीश सिंह खेहर ने श्री रामनाथ कोविंद को देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित भव्य समारोह में 25 जुलाई को दोपहर सवा बारह बजे शपथ दिलाई। बाद में मंच पर निवर्तमान राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी और नए राष्ट्रपति के बीच कुर्सियों की अदला–बदली हुई। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि उनका मूल मंत्र है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।

शपथ ग्रहण के बाद नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने समारोह को सम्बोधित भी किया। 71 वर्षीय श्री कोविंद इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पहले व्यक्ति है। राजग ने श्री कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था और वह 17 विपक्षी दलों की उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार को भारी मतों से हराकर राष्ट्रपति चुने गए।

शपथ ग्रहण समारोह में केन्द्रीय कक्ष में राज्य सभा के सभापति श्री हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच. डी. देवगौड़ा और श्री मनमोहन सिंह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, केन्द्रीय मंत्री परिषद के सदस्य, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, विदेशी दूतावासों के प्रमुख, सांसद और शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद थे। शपथ के बाद नए राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है और मैं इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहा हूं।

श्री कोविंद संसद भवन से निकलने के बाद श्री मुखर्जी के साथ ही राष्ट्रपति भवन गए। वहां उन्होंने एक रजिस्टर में हस्ताक्षर किए। इसके बाद राष्ट्रपति बग्गी से राष्ट्रपति भवन परिसार की पोर्टिको पहुंचे, जहां पहले से ही उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, के अलावा कई केन्द्रीय मंत्री और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वहां श्री कोविंद को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। बाद में श्री मुखर्जी को भी बग्गी से पोर्टिको लाया गया। उन्होंने भी सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों की सलामी ली। श्री मुखर्जी ने बाद में सभी से विदाई ली और नए राष्ट्रपति उन्हें उनके नए आवास 10 राजाजी मार्ग पहुंचाने गए। ■

@narendramodi

रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई। उन्हें फलदायक और प्रेरणादायक कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। मैं सांसदों और विभिन्न दलों के बीच रामनाथ कोविंद को मिले व्यापक समर्थन से हर्षित हूं। मैं निर्वाचक मंडल के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।
– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

जीवन–वृत्त

सार्वजनिक जीवन और समाज में समतावाद तथा अखण्डता के पैरोकार रहे वकील, वरिष्ठ राजनेता श्री रामनाथ कोविंद का जन्म 01 अक्टूबर, 1945 को उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट परौंख में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री मैकूलाल और माता का नाम श्रीमती कलावती था। 25 जुलाई, 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री कोविंद ने 16 अगस्त, 2015 से 20 जून, 2017 तक बिहार के 36वें राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी ।

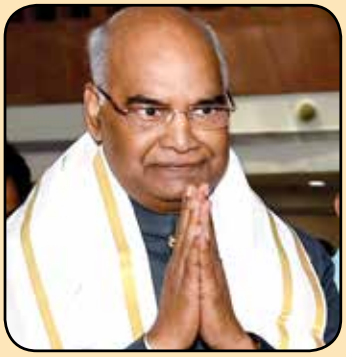

शैक्षिक योग्यता और व्यावसायिक पृष्ठभूमि

श्री कोविंद ने अपनी स्कूली शिक्षा कानपुर में ग्रहण की और कानपुर विश्वविद्यालय से बी.कॉम तथा एलएलबी की डिग्री हासिल की। 1971 में उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकन किया। श्री कोविंद 1977 से लेकर 1979 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में केन्द्र सरकार के वकील रहे तथा 1980 से 1993 तक उच्चतम न्यायालय में केन्द्र सरकार के वकील रहे। 1978 में वे उच्चतम न्यायालय के 'एडवोकेट-ऑन-रिकार्ड' बने। 1993 तक उन्होंने कुल 16 साल तक दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में वकालत की।

संसदीय और सार्वजनिक जीवन

श्री कोविंद को अप्रैल, 1994 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य चुना गया। उन्होंने लगातार दो बार राज्य सभा के सदस्य के रूप में मार्च, 2006 तक कार्य किया। श्री कोविंद ने विभिन्न संसदीय समितियों जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति, गृह मामलों की संसदीय समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर संसदीय समिति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति और कानून और न्याय संबंधी संसदीय समितियों में सेवा की। वह राज्य सभा हाउस कमेटी के चेयरमैन भी रहे। श्री कोविंद भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं उत्तर प्रदेश भाजपा के महामंत्री का दायित्व सम्भाल चुके हैं।

श्री कोविंद बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता के बोर्ड ऑफ गवर्नस के सदस्य भी रहे। वह संयुक्त राष्ट्र में गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी रहे और अक्टूबर, 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया।

इन पदों पर किया कार्य

2015-17: बिहार के राज्यपाल
1994-2006: उत्तर प्रदेश से राज्य सभा सदस्य
1971-75 और 1981: महासचिव, अखिल भारतीय कोली समाज
1977-79: दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील
1982-84: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के अधिवक्ता

व्यक्तिगत विवरण

श्री कोविंद का विवाह 30 मई, 1974 को श्रीमती सविता कोविंद से हुई। श्री कोविंद के पुत्र का नाम श्री प्रशांत कुमार और पुत्री का नाम सुश्री स्वाति है। पढ़ने-लिखने के शौकीन राष्ट्रपति श्री कोविंद को राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों, कानून और इतिहास तथा धर्म संबंधी किताबें पढ़ने में गहरी दिलचस्पी है।

अपने लम्बे सार्वजनिक जीवन के दौरान श्री कोविंद ने कई देशों की यात्रा की है। संसद सदस्य के रूप में उन्होंने थाईलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा भी किया है। ■

@AmitShah

यह 'गरीबों, दलितों और वंचितों की व उनकी आकांक्षाओं की जीत' है। कोविंद देश के असाधारण राष्ट्रपति के तौर पर खुद को साबित करेंगे। उनकी जीत ऐतिहासिक है।

— अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष

समर्थन पर प्रसन्नता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार को उनके अभियान के लिए बधाई दी और कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की भावना के अनुरूप रहा।

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने श्री कोविंद को राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके उत्तराधिकारी देश को खुशहाली और लोकतंत्र के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। श्री मुखर्जी ने अपने संदेश में कहा कि भारत गणराज्य के 14वें राष्ट्रपति के रूप में आपके निर्वाचन पर मैं आपको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं।

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में बारिश के बीच अपने बचपन के 'कच्चे' घर को याद किया। देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री कोविंद ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की रक्षा करना और इसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखना उनका कर्त्तव्य होगा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी राष्ट्रपति बनने के बारे में न तो सोचा था और न कल्पना की थी, लेकिन समाज और देश की उनकी 'अथक सेवा' उनको इस पद तक लेकर आई है। श्री कोविंद ने अपने अकबर रोड स्थित आवास पर कहा कि अथक सेवा की यह भावना 'भारतीय परंपरा' है और उनका निर्वाचन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है।

निर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि आज देश में ऐसे बहुत सारे रामनाथ कोविंद होंगे जो बारिश में भीग रहे होंगे, खेती का काम कर रहे होंगे, मजदूरी कर रहे होंगे और पसीना बहा रहे होंगे, ताकि शाम में उनको भोजन मिल सके। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद उनके प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति भवन जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी जैसे व्यक्तित्व इस पद पर रहे और अब इस पद के लिए अपने निर्वाचन को वे अपने लिए बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं।

संस्कृत के एक श्लोक को उद्धृत करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि वे देश की सेवा और सबको खुश करने के लिए अथक रूप से काम करेंगे। श्री कोविंद ने अपनी प्रतिद्वंद्वी श्रीमती मीरा कुमार को शुभकामना दी।

कानपुरवासी श्री कोविंद ने देश के प्रथम नागरिक के रूप में निर्वाचित होकर नई तारीख लिख दी है। उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के चुनाव में एक जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के परौंख गांव स्थित उनके पैतृक आवास में जश्न का माहौल रहा। ■

देश की सफलता का मंत्र उसकी विविधता में है: रामनाथ कोविन्द

भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के अवसर पर श्री रामनाथ कोविन्द ने 25 जुलाई को एक सारगर्भित भाषण दिया। इस भाषण का पूरा पाठ हम सुधी पाठकों के लिए यहां प्रकाशित कर रहे हैं:

मुझे, भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ इस पद को ग्रहण कर रहा हूं। यहां सेंट्रल हॉल में आकर मेरी कई पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई हैं। मैं संसद का सदस्य रहा हूं, और इसी सेंट्रल हॉल में मैंने आप में से कई लोगों के साथ विचार-विनिमय किया है। कई बार हम सहमत होते थे, कई बार असहमत, लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।

मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला-बढ़ा हूं। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है। हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। हर चुनौती के बावजूद, हमारे देश में, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है और मैं इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहूंगा।

मैं इस महान राष्ट्र के 125 करोड़ नागरिकों को नमन करता हूं और उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का मैं वचन देता हूं। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि मैं डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और मेरे पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जी, जिन्हें हम स्नेह से 'प्रणब दा' कहते हैं, जैसी विभूतियों के पदचिह्नों पर चलने जा रहा हूं।

हमारी स्वतंत्रता, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का परिणाम थी। बाद में सरदार पटेल ने हमारे देश का एकीकरण किया। हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने हम सभी में मानवीय गरिमा और गणतांत्रिक मूल्यों का संचार किया।

वे इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही काफी है। उनके लिए, हमारे करोड़ों लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को पाना भी बहुत महत्त्वपूर्ण था। अब स्वतंत्रता मिले 70 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में हैं, वो सदी, जिसके बारे में हम सभी को भरोसा है कि ये भारत की सदी होगी, भारत की उपलब्धियां ही इस सदी की दिशा और स्वरूप तय करेंगी। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक नेतृत्व देने के साथ ही नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत करे। हमारे लिए ये दोनों मापदंड कभी अलग नहीं हो सकते। ये दोनों जुड़े हुए हैं और इन्हें हमेशा जुड़े ही रहना होगा।

देश की सफलता का मंत्र उसकी विविधता है। विविधता ही हमारा वो आधार है, जो हमें अद्वितीय बनाता है। इस देश में हमें राज्यों और क्षेत्रों, पंथों, भाषाओं, संस्कृतियों, जीवन-शैलियों जैसी कई बातों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। हम बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी एक हैं और एकजुट हैं।

21वीं सदी का भारत, ऐसा भारत होगा जो हमारे पुरातन मूल्यों के अनुरूप होने के साथ ही साथ चौथी औद्योगिक क्रांति को विस्तार देगा। इसमें ना कोई विरोधाभास है और ना ही किसी तरह के विकल्प का प्रश्न उठता है। हमें अपनी परंपरा और प्रौद्योगिकी, प्राचीन भारत के ज्ञान और समकालीन भारत के विज्ञान को साथ लेकर चलना है।

एक तरफ जहां ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक भावना से विचार-विमर्श करके समस्याओं का निस्तारण होगा, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल राष्ट्र हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में सहायता करेगा। ये हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के दो महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं।

राष्ट्र निर्माण अकेले सरकारों द्वारा नहीं किया जाता। सरकार सहायक हो सकती है, वो समाज की उद्यमी और रचनात्मक प्रवृत्तियों को दिशा दिखा सकती है, प्रेरक बन सकती है। राष्ट्र निर्माण का आधार है— **राष्ट्रीय गौरव :**

- हमें गर्व है—भारत की मिट्टी और पानी पर;
- हमें गर्व है—भारत की विविधता, सर्वधर्म समभाव और समावेशी विचारधारा पर;
- हमें गर्व है—भारत की संस्कृति, परंपरा एवं अध्यात्म पर;
- हमें गर्व है—देश के प्रत्येक नागरिक पर;
- हमें गर्व है—अपने कर्त्तव्यों के निवर्हन पर और
- हमें गर्व है—हर छोटे से छोटे काम पर, जो हम प्रतिदिन करते हैं।

देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे।

- देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और हमें सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र बल, राष्ट्र निर्माता हैं।
- जो पुलिस और अर्धसैनिक बल, आतंकवाद और अपराधों से लड़ रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता हैं।
- जो किसान तपती धूप में देश के लोगों के लिए अन्न उपजा रहा है,

वो राष्ट्र निर्माता है और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, कि खेत में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम करती हैं।

- जो वैज्ञानिक 24 घंटे अथक परिश्रम कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन को मंगल तक ले जा रहा है, या किसी वैक्सीन का अविष्कार कर रहा है, वो राष्ट्र निर्माता है।
- जो नर्स या डॉक्टर सुदूर किसी गांव में, किसी मरीज की गंभीर बीमारी से लड़ने में उसकी मदद कर रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं।
- जिस नौजवान ने अपना स्टार्ट-अप शुरू किया है और अब स्वयं रोजगार दाता बन गया है, वो राष्ट्र निर्माता है। ये स्टार्ट-अप कुछ भी हो सकता है। किसी छोटे से खेत में आम से अचार बनाने का काम हो, कारीगरों के किसी गांव में कार्पेट बुनने का काम हो या फिर कोई लैबोरेटरी, जिसे बड़ी स्क्रीनों से रौशन किया गया हो।
- वो आदिवासी और सामान्य नागरिक, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में हमारे पर्यावरण, हमारे वनों, हमारे वन्य जीवन की रक्षा कर रहे हैं और वे लोग जो नवीकरणीय ऊर्जा के महत्त्व को बढ़ावा दे रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं।

हमें तेजी से विकसित होने वाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक शिक्षित, नैतिक और साझा समुदाय, समान मूल्यों वाले और समान अवसर देने वाले समाज का निर्माण करना होगा। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। ये हमारे मानवीय मूल्यों के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं। ये हमारे सपनों का भारत होगा।

- वो प्रतिबद्ध लोकसेवक जो पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं, कहीं पानी से भरी सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे हैं, कहीं किसी कमरे में बैठकर फाइलों पर काम कर रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं।
- वो शिक्षक, जो निःस्वार्थ भाव से युवाओं को दिशा दे रहे हैं, उनका भविष्य तय कर रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं।
- वो अनगिनत महिलाएं जो घर पर और बाहर, तमाम दायित्व निभाने के साथ ही अपने परिवार की देख-रेख कर रही हैं, अपने बच्चों को देश का आदर्श नागरिक बना रही हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं।

देश के नागरिक ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उन प्रतिनिधियों में अपनी आस्था और उम्मीद जताते हैं। नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए यही जनप्रतिनिधि अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में लगाते हैं।

लेकिन हमारे ये प्रयास सिर्फ हमारे लिए ही नहीं हैं। सदियों से भारत ने वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है, के दर्शन पर भरोसा किया है। ये उचित होगा कि अब भगवान बुद्ध की ये धरती, शांति की स्थापना और पर्यावरण का संतुलन बनाने में विश्व का नेतृत्व करे।

आज पूरे विश्व में भारत के दृष्टिकोण का महत्त्व है। पूरा विश्व भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं की तरफ आकर्षित है। विश्व समुदाय अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए हमारी तरफ देख रहा है। चाहे आतंकवाद हो, कालेधन का लेन-देन हो या फिर जलवायु परिवर्तन। वैश्विक परिदृश्य में हमारी जिम्मेदारियां भी वैश्विक हो गई हैं।

यही भाव हमें, हमारे वैश्विक परिवार से, विदेश में रहने वाले मित्रों और सहयोगियों से, दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में रहकर अपना योगदान दे रहे प्रवासी भारतीयों से जोड़ता है। यही भाव हमें दूसरे देशों की सहायता के लिए तत्पर करता है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का विस्तार करना हो, या फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय, सबसे पहले सहयोग के लिए आगे आना हो।

एक राष्ट्र के तौर पर हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इससे भी और अधिक करने का प्रयास और बेहतर करने का प्रयास, और तेजी से करने का प्रयास, निरंतर होते रहना चाहिए। ये इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022 में देश अपनी स्वतंत्रता के 75वें साल का पर्व मना रहा होगा। हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए, और गरीब परिवार की उस आखिरी बेटी के लिए भी नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खुलें। हमारे प्रयत्न आखिरी गांव के आखिरी घर तक पहुंचने चाहिए। इसमें न्याय प्रणाली के हर स्तर पर, तेजी के साथ, कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया जाना चाहिए।

इस देश के नागरिक ही हमारी ऊर्जा का मूल स्रोत हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि राष्ट्र की सेवा के लिए, मुझे इन लोगों से इसी प्रकार निरंतर शक्ति मिलती रहेगी।

हमें तेजी से विकसित होने वाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक शिक्षित, नैतिक और साझा समुदाय, समान मूल्यों वाले और समान अवसर देने वाले समाज का निर्माण करना होगा। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। ये हमारे मानवीय मूल्यों के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं। ये हमारे सपनों का भारत होगा। एक ऐसा भारत, जो सभी को समान अवसर सुनिश्चित करेगा। ऐसा ही भारत, 21वीं सदी का भारत होगा। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद!! जय हिन्द!! वंदे मातरम्!! ■

राजग के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बने वेंकैया नायडू

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री एम.वेंकैया नायडू को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से 17 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की अध्यक्षता में संपन्न पार्टी संसदीय दल की बैठक में श्री नायडू के नाम की घोषणा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे।

श्री शाह ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'वेंकैयाजी देश के वरिष्ठ नेताओं में हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जो युवाकाल से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्हें भाजपा तथा राजग द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया है। राजग के सभी सदस्यों ने उपराष्ट्रपति पद के लिए श्री वेंकैया नायडू की उम्मीदवारी का स्वागत किया है।'

उन्होंने कहा कि श्री नायडू एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, जिनकी उम्मीदवारी का राजग के सभी नेताओं ने स्वागत किया है। श्री नायडू दो बार भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं और चार बार से राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा कि श्री नायडू अपने युवाकाल से ही भाजपा से जुड़े रहे हैं और वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के नेता तथा छात्रसंघ के नेता थे। वह जयप्रकाश आंदोलन से भी जुड़े और आंध्र प्रदेश से दो बार विधायक तथा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बने।

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री वेंकैया नायडू ने 18 जुलाई को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ■

किसान के बेटे वेंकैया नायडू के पास लंबा संसदीय अनुभव है, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में उनकी मदद करेगा। पूरी राजनीतिक बिरादरी में उन्हें सराहा जाता है। वह उपराष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

देश की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने में सरकार सफल हुई है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने तीन दिवसीय राजस्थान प्रवास के पहले दिन 22 जुलाई को बिड़ला ऑडिटोरियम, राजस्थान में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सिद्धांत और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों व मोदी सरकार द्वारा राजस्थान के विकास के लिए किये जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की।

इससे पहले श्री शाह ने प्रदेश कार्यालय, जयपुर में नानाजी देशमुख ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके बाद श्री शाह ने राजस्थान प्रदेश कोर कमिटी के सदस्यों, सांसदों, विधायकों, प्रदेश कार्यालय पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों एवं जिला महासचिवों के साथ बैठक की और केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा मुद्दों पर चर्चाएं भी कीं। साथ ही उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी कार्यक्रम एवं कार्य विस्तारक योजना की भी समीक्षा बैठक की।

भारतीय जनता पार्टी और देश की अन्य पार्टियों में अंतर क्या है, इस पर चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि आज देश के राजनीतिक दलों की विचारधारा, दलों के आतंरिक लोकतंत्र और सरकार बनने के बाद की परफोर्मेंस का तुलनात्मक अध्ययन करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह बहुत जरूरी है कि उस देश के राजनीतिक दलों में भी आतंरिक लोकतंत्र मजबूत हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देश की लगभग 1650 छोटी-बड़ी पार्टियों में से केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके अंदर आतंरिक लोकतंत्र मजबूत है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है तो वह देश का भला कभी नहीं कर सकती लेकिन यदि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र तो देश का लोकतंत्र भी मजबूत बना रहता है। उन्होंने कहा कि देश की अधिकतर पार्टियों में सबको पता है कि उसका अगला अध्यक्ष कौन होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, यह सब लोगों को पता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य कौन होगा, यह किसी को मालूम नहीं है। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कितना मजबूत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष वंश परंपरा अथवा जाति के आधार पर तय नहीं होते, बल्कि योग्यता, पार्टी के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा और परिश्रम के आधार पर तय होते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां एक बूथ कार्यकर्ता भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है और एक गरीब परिवार का बेटा व पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि जहां लोकतंत्र मजबूत होता है, वहां योग्यता के आधार पर फैसले होते हैं, वहां बदलाव की गुंजाइश होती है और जहां बदलाव की गुंजाइश होती है, वहां कभी भी डिमेरिट्स को स्थान नहीं मिलता।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि किसी पार्टी के मूल्यांकन करने का तीसरा महत्वपूर्ण मानक है कि जब कोई पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है तो उसका परफॉरमेंस किस तरह का रहता है। उन्होंने कहा

कि इस मानक पर भी भारतीय जनता पार्टी ने देश में उच्चतम मापदंड स्थापित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई सिद्धांत ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसी सिद्धांत अथवा विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि आजादी को प्राप्त करने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए सभी विचारधाराओं वाले लोग कांग्रेस में शामिल हुए और इसलिए महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर विचारधारा के आधार पर पार्टी के गठन करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है, वह देश का विकास नहीं कर सकती।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जन संघ की विचारधारा में एक बड़ा मूल अंतर यह था कि कांग्रेस देश का नवनिर्माण करना चाहती थी, जबकि भारतीय जन संघ देश की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली वैभव के आधार पर देश का पुनर्निर्माण करना चाहती थी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के बाद देश में 70 सालों तक जो सरकारें चली हैं, उसमें देश की जनता ने चार प्रकार की सरकारें देखी है - कांग्रेस पार्टी की सरकारें, कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकारें,

क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। प्रबुद्ध जनों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अब देश में तुलनात्मक अध्ययन करने का समय आ गया है। चारों प्रकार के विकास के मॉडल देश की जनता के सामने है, उन्हें यह देखना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारों में क्या विकास हुआ है, कम्युनिस्ट की राज्य सरकारों में कैसा विकास हुआ है, क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारों के राज्य में कैसा विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कैसा विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन-जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहीं, वहां हमने विकास के नए मापदंड स्थापित किये और विकास की नई परिभाषा स्थापित की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार लोकाभिमुख, पारदर्शी और निर्णायक होती है।

श्री शाह ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी देश की 60% आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं था। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत तीन वर्ष में ही देश के लगभग 28.5 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए। उन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट खोलने के बाद सरकार ने लाभार्थियों की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जिससे सरकार ने हजारों करोड़ रुपये की चोरी बचाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के पांच करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है जिसमें से लगभग 2 करोड़ 60 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरित किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी देश के लगभग 12 करोड़ परिवार ऐसे थे, जिनके घर में टॉयलेट्स तक नहीं थे। हमने तीन ही साल में साढ़े चार करोड़ टॉयलेट्स बनाने का काम ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने खुले में शौच से मुक्ति का मुहिम शुरू कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक के माध्यम से मोदी सरकार देश के 7.64 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का काम किया है।

श्री शाह ने कहा कि काले-धन के दुष्प्रभाव को देश की अर्थव्यवस्था से ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का सफल और साहसिक कदम उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने में सरकार सफल हुई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक चंदों को 2000 कैश तक सीमित करके राजनीतिक पार्टियों की चंदे की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि चाहे बेनामी संपत्ति पर क़ानून की बात हो, शत्रु संपत्ति बिल को पारित कराने की बात हो या फिर फर्जी कंपनियों के खिलाफ मुहिम की बात - केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर मोर्चे पर अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए इन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि साइप्रस, सिंगापुर और मॉरीशस के रूट से जो काला-धन देश में आता था, उसे बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सबका परिणाम है कि एक ही साल में लगभग 91 लाख नए पैन कार्ड रजिस्टर हुए हैं। श्री शाह ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार आने के पहले जो परिस्थितियां थी, वह 2017 में बिलकुल बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन की सरकार पर 12 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप थे और अब केंद्र में तीन साल से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को ख़त्म कर देश में पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस के एक नए युग की शुरुआत की है।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को 'अच्छा लगे' इस अभियान में नहीं लगी रहती, बल्कि लोगों के लिए 'अच्छा हो', ऐसे अभियान में लगी रहती है, इसीलिए देश तीव्र गति से विकास करता दिखाई दे रहा है। प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत और वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान जिस प्रकार से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है तथा भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आपके आशीर्वाद से इसी तरह चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम भारत माता को विश्व गुरु के रूप में पुनर्प्रतिष्ठित करने में सफल होंगे । ■

'राज्य में गरीब तबकों को आगे बढ़ाने के सराहनीय प्रयास हुए'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने तीन दिवसीय राजस्थान प्रवास के दौरान प्रदेश कार्यालय, जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों के प्रश्नों का विस्तार से जवाब दिया और राजस्थान में भाजपा की सरकार पुनः बनाने का संकल्प व्यक्त किया। इससे पूर्व श्री शाह ने प्रदेश कार्यालय में ही प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों और मोर्चा प्रमुखों, प्रकल्प व प्रकोष्ठ प्रभारियों के अतिरिक्त प्रदेश से लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों के साथ भी बैठक कर उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एक ही वर्ष में देश के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर में 18% की वृद्धि हुई जो आज़ादी के बाद सर्वाधिक है। नोटबंदी का फैसला अपने आप में एक ऐतिहासिक व साहसिक फैसला था, जिसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। अंतरिक्ष में एक साथ 104 उपग्रह को स्थापित करने का भारतीय वैज्ञानिकों का पराक्रम भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने वाला है। उज्ज्वला योजना के तहत ढाई करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने का काम किया गया और इसी योजना के तहत राजस्थान में 20 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन बांटे गए। जनधन योजना के तहत देश में 28.56 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, जिसमें अब तक 64,682 करोड़ रूपया गरीबों ने जमा किये। अकेले राजस्थान में 2 करोड़ से ज्यादा बैंक खुलवाकर गरीबों को अर्थतंत्र से जोड़ने का प्रयास किया गया। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 7 करोड़ 74 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगारी देने का काम किया गया है और इसके लिए करीब 4 लाख करोड़ ऋण आवंटित किये गए हैं। अकेले राजस्थान में 26 लाख बेरोजगार युवाओं को 10 हज़ार-10 लाख तक का ऋण देने का काम करते हुए इसके तहत अब तक 15,711 करोड़ का कुल ऋण आवंटित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया, स्वायल हेल्थ कार्ड, ई-मंदी, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और कुदरती आपदा के समय किसानों को सहायता में वृद्धि करने का बड़ा काम भाजपा सरकार ने किया हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में 13वें वित्त आयोग ने सेन्ट्रल टेक्स में राजस्थान की हिस्सेदारी 84,426 करोड़ रुपये थी, जबकि मोदी सरकार में 14वें वित्त आयोग में यह 2,18,145 करोड़ रुपये हो गयी है अर्थात तीन गुना ज्यादा । राजस्थान को अनुदान सहायता राशि जो पहले 13,108 करोड़ रुपये दी जाती थी उसकी जगह 14वें वित्त आयोग में 22,717 करोड़ दी जाती है जो डेढ़ गुणा ज्यादा है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि जो पहले 2,489 करोड़ रुपये थी, अब उसे दोगुना बढाकर 4,570 करोड़ रूपया कर दिया गया है। लोकल बॉडीज ग्रांट्स जो पहले 5,262 करोड़ थी उसे बढ़ाकर 18,147 अर्थात 3 गुना बढ़ाया गया है। श्री शाह ने राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए चलाये गए भामा शाह योजना, भामा शाह स्वास्थ्य योजना, राशन वितरण के अन्तर्गत 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की बायो मीट्रिक पहचान द्वारा करप्शन ख़त्म करने की योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, न्याय आपके द्वार, अन्नपूर्णा भंडारण योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण पंचायत शिविर जैसी विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये योजनायें राजस्थान के गरीब तबकों को आगे बढ़ाने के सराहनीय प्रयास हैं।

श्री शाह ने कहा कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी जी और राजस्थान में वसुंधरा राजे जी की सरकार, दोनों मिलकर देश-प्रदेश के लिए एक ग्रोथ इंजन का काम कर रहे हैं और हम अगले तीन-चार महीनों में राजस्थान के संगठन और राजस्थान भाजपा को अजेय स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे। ■

किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार के बहुआयामी कदम

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। ये निम्न हैं-

- सॉयल हेल्थ कार्ड (एसएचसी) योजना जिससे किसान अपनी मिट्टी में उपलब्ध बड़े और छोटे पोषक तत्वों का पता लगा सकते हैं। इससे उर्वरकों का उचित प्रयोग करने और मिट्टी की उर्वरता सुधारने में मदद मिलेगी।
- नीम कोटिंग वाले यूरिया को बढ़ावा दिया गया है ताकि यूरिया के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जा सके, फसल के लिए इसकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके और उर्वरक की लागत कम की जा सके। घरेलू तौर पर निर्मित और आयातित यूरिया की संपूर्ण मात्रा अब नीम कोटिंग वाली है।
- परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) को लागू किया जा रहा है, ताकि देश में जैव कृषि को बढ़ावा मिल सके। इससे मिट्टी की सेहत और जैव पदार्थ तत्वों को सुधारने तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई (पीएमकेएसवाई) योजना को लागू किया जा रहा है ताकि सिंचाई वाले क्षेत्र को बढ़ाया जा सके, जिसमें किसी भी सूरत में सिंचाई की व्यवस्था हो, पानी की बर्बादी कम हो, पानी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके।

राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना (ई-एनएएम) की शुरुआत 14.04.2016 को की गई थी। इस योजना से राष्ट्रीय स्तर पर ई-विपणन मंच की शुरुआत हो सकेगी और ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार होगा, जिससे देश के 585 नियमित बाजारों में मार्च 2018 तक ई-विपणन की सुविधा हो सकेगी। अब तक 13 राज्यों के 455 बाजारों को ई-एनएएम से जोड़ा गया है। यह नवाचार विपणन प्रक्रिया बेहतर मूल्य दिलाने, पारदर्शिता लाने और प्रतिस्पर्धा कायम करने में मदद करेगी, जिससे किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर पारिश्रमिक मिल सकेगा और 'एक राष्ट्र एक बाजार' की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को खरीफ मौसम 2016 से लागू किया गया और यह कम प्रीमियम पर किसानों के लिए उपलब्ध है। इस योजना से कुछ मामलो में कटाई के बाद के जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

सरकार 3 लाख रुपये तक के अल्प अवधि फसल ऋण पर 3 प्रतिशत दर से ब्याज रियायत प्रदान करती है। वर्तमान में किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से ऋण उपलब्ध है, जिसे तुरन्त भुगतान करने पर 4 प्रतिशत तक कम कर दिया जाता है। ब्याज रियायत योजना 2016-17 के अंतर्गत, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज रियायत पहले वर्ष के लिए बैंकों में उपलब्ध रहेगी। किसानों द्वारा मजबूरी में अपने उत्पाद बेचने को हतोत्साहित करने और उन्हें

अपने उत्पाद भंडार गृहों की रसीद के साथ भंडार गृहों में रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे छोटे और मझौले किसानों को ब्याज रियायत का लाभ मिलेगा, जिनके पास फसल कटाई के बाद के 6 महीनों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होंगे।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को सरकार उनकी जरूरतों के मुताबिक राज्यों में लागू कर सकेगी, जिसके लिए राज्य में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। राज्यों को उनकी जरूरतों, प्राथमिकताओं और कृषि-जलवायु जरूरतों के अनुसार योजना के अंतर्गत परियोजनाओं/कार्यक्रमों के चयन, योजना की मंजूरी और उन्हें अमल में लाने के लिए लचीलापन और स्वयतत्ता प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 29 राज्यों के 638 जिलों में एनएफएसएम दाल, 25 राज्यों के 194 जिलों में एनएफएसएम चावल, 11 राज्यों के 126 जिलों में एनएफएसएम गेहूं और देश के 28 राज्यों के 265 जिलों में एनएफएसएम मोटा अनाज लागू की गई है ताकि चावल, गेहूं, दालों, मोटे अनाजों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। एनएफएसएम के अंतर्गत किसानों को बीजों के वितरण (एचवाईवी/हाईब्रिड), बीजों के उत्पादन (केवल दालों के), आईएनएम और आईपीएम तकनीकों, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों/उपकणों, प्रभावी जल प्रयोग साधन, फसल प्रणाली जो किसानों को प्रशिक्षण देने पर आधारित है, को लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय तिलहन और तेल (एनएमओओपी) मिशन कार्यक्रम 2014-15 से लागू है। इसका उद्देश्य खाद्य तेलों की घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। इस मिशन की विभिन्न कार्यक्रमों को राज्य कृषि/बागवानी विभाग के जरिये लागू किया जा रहा है।

बागवानी के समन्वित विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच), केन्द्र प्रायोजित योजना फलों, सब्जियों के जड़ और कन्द फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंध वाले वनस्पति, नारियल, काजू, कोको और बांस सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2014-15 से लागू है। इस मिशन में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और बागवानी के लिए केन्द्रीय संस्थान, नागालैंड को शामिल कर दिया गया है।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अन्य कदम इस प्रकार हैः-

- सरकार ने कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2017 को तैयार किया, जिसे राज्यों के संबद्ध अधिनियमों के जरिये उनके द्वारा अपनाने के लिए 24.04.2017 को जारी कर दिया गया। यह अधिनियम निजी बाजारों, प्रत्यक्ष विपणन, किसान उपभोक्ता बाजारों, विशेष वस्तु बाजारों सहित वर्तमान एपीएमसी नियमित बाजार के अलावा वैकल्पिक बाजारों का विकल्प प्रदान करता है, ताकि उत्पादक और खरीददार के बीच बिचौलियों की संख्या कम की जा सके और उपभोक्ता के रुपए में किसान का हिस्सा बढ़ सके।
- सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत गेहूं और धान की खरीद करती है। सरकार ने राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के अनुरोध पर कृषि और बागवानी से जुड़ी उन वस्तुओं की खरीद के लिए बाजार हस्ताक्षेप योजना लागू की है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाजार हस्ताक्षेप योजना इन फसलों की पैदावार करने वालों को संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू की गई है, ताकि वह अच्छी फसल होने पर मजबूरी में कम दाम पर अपनी फसलों को न बेचें।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ और रबी दोनों तरह की फसलों के लिए अधिसूचित होता है जो कृषि आयोग की लागत और मूल्यों के बारे में सिफारिशों पर आधारित होता है। आयोग फसलों की लागत के बारे में आंकड़ें एकत्र करके उनकी विश्लेषण करता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। देश में दालों और तिलहनों की फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीफ 2017-18 के लिए बोनस की घोषणा की है। सरकार ने पिछले वर्ष भी दालों और तिलहनों के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देने की पेशकश की थी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ और रबी दोनों तरह की फसलों के लिए अधिसूचित होता है जो कृषि आयोग की लागत और मूल्यों के बारे में सिफारिशों पर आधारित होता है। आयोग फसलों की लागत के बारे में आंकड़ें एकत्र करके उनकी विश्लेषण करता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। देश में दालों और तिलहनों की फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीफ 2017-18 के लिए बोनस की घोषणा की है।

- सरकार के नेतृत्व में बाजार संबंधी अन्य हस्तक्षेप जैसे मूल्य स्थिरीकरण कोष और भारतीय खाद्य निगम का संचालन भी किसानों की आमदनी बढ़ाने का अतिरिक्त प्रयास है।
- उपरोक्त के अलावा सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मधु मक्खियां रखने जैसे क्रियाकलापों पर ध्यान दे रही है। ■

खुदरा मुद्रास्फीति 1.54% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर

सब्जी, दाल और दुग्ध उत्पादों के दाम घटने से जून में खुदरा महंगाई दर घटकर 1.54% पर आ गई। यह मई में 2.18% और पिछले साल जून में 5.77 फीसदी पर थी। जून में सब्जियों की कीमतें 16.53% और दालों की कीमतें 21.92% कम हुईं। अनाज के दाम 4.39% और दुग्ध उत्पादों के 4.15% कम हुए। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा 12 जुलाई को जारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य पदार्थों की महंगाई दर घटकर शून्य से नीचे 2.12% दर्ज हुई है। मई में यह शून्य से नीचे 1.05% थी। इसी तरह ईंधन और बिजली की महंगाई दर जून में घटकर 4.54% पर आ गई। मई में यह 5.46% थी। मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अरविंद सुब्रमणियन ने कहा कि नीति निर्माताओं को इन आंकड़ों को सावधानीपूर्वक देखना चाहिए। इससे पहले इतनी कम महंगाई (इंडस्ट्रियल वर्कर) 1999 और 1978 में देखने को मिली थी।

सामान्य सूचकांकों और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांकों के आधार पर राष्ट्रीय मुद्रास्फीति दर (पिछले वर्ष के महीने की तुलना वर्तमान वर्ष के समान महीने से अर्थात् जून 2016 की तुलना में जून 2017) निम्न तालिका में दी गई है:-

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित राष्ट्रीय मुद्रा स्फीति दर (%)

सूचकांक	जून 2017 अस्थायी			मई 2017 (अन्तिम)			जून 2016 (अन्तिम)		
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य)	1.59	1.41	1.54	2.30	2.13	2.18	6.29	5.26	5.77
उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक	-1.62	-3.16	-2.12	-0.60	-1.85	-1.05	7.69	8.16	7.79

पटसन किसानों की आय 10,000 रुपये से अधिक बढ़ी

बेहतर कृषि आर्थिक व्यवहारों को लोकप्रिय बनाने/ प्रचलित करने के लिए वर्ष 2015 में लांच की गई पहल जूट के लिए बेहतर खेती और आधुनिक आर्द्रता (जूट-आईकेयर) ने हाल में पायलट आधार पर पश्चिम बंगाल और असम के कुछ ब्लॉकों में किसानों के बीच माइक्रो बायल समर्थित नमी अभ्यास किया। संशोधित कृषि आर्थिक व्यवहार में पैदावार 10-15 प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्यारीबद्ध तरीके से पटसन की बुआई, खर-पतवार प्रबंधन लागत में कमी के लिए हाथ की जगह मशीनों से खर-पतवार प्रबंधन शामिल हैं।

जूट और संबद्ध रेशा अनुसंधान के लिए केन्द्रीय अनुसंधान संगठन (सीआरआईजेएएफ) ने सोना नामक माइक्रोबायरल कंर्सोटियम विकसित किया है, ताकि रेशे की उत्पादकता 20 प्रतिशत बढ़ाई जा सके और गुणवत्ता की दृष्टि से इसमें डेढ़ ग्रेड वृद्धि की जा सके। जूट उत्पादकता में सुधार पर पंजीकृत किसानों को क्षेत्रीय भाषाओं में एसएमएस भेजे जाते हैं। परियोजना के दौरान विभिन्न अंतरालों पर प्रत्येक किसान को औसतन 50 एसएमएस भेजे जाते हैं। प्रदर्शनी उद्देश्य से बीज छेदन यंत्र और खत-पतवार प्रबंधन यंत्र भेजे गए हैं।

इन पहलों से प्रति हेक्टेयर पटसन किसानों की आय 10,000 रुपये से अधिक बढ़ी है। जूट आई-केयर पायलट परियोजना के उत्साही परिणामों को देखते हुए राज्य कृषि विस्तार व्यवस्था के माध्यम से जूट आई-केयर कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए कपड़ा मंत्री और कृषि मंत्री द्वारा 22.3.2017 को संयुक्त बैठक की गई। इस बैठक में राज्य सरकारों, कृषि अनुसंधान एजेंसियों, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, राष्ट्रीय पटसन निगम के प्रतिनिधि शामिल हुए। जूट आई-केयर कार्यक्रम के अंतर्गत उठाये कुछ कदम इस प्रकार हैं:

- सभी मुख्य मंत्रियों को सलाह दी गई है कि वे जूट आई-केयर कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत लें और कृषि विकास केंद्रों (केवीके) के माध्यम से प्रमाणित पटसन बीज उपयोग के लिए किसानों को जागरूक बनायें। राज्यों से कृषि मिशन में उप-मिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत कृषि उपकरणों की सप्लाई करने और मनरेगा तथा आरकेवीवाई के अंतर्गत नमी के लिए टैंक बनाने का भी अनुरोध किया गया है।
- 22 मई, 2017 को वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय पटसन बोर्ड ने राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय पटसन निगम के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह ज्ञापन 2018 के लिए पटसन किसानों को 800 मीट्रिक टन नए किस्म के पटसन बीज और 2019 के लिए 1500 मीट्रिक टन नए किस्म के पटसन बीज की सप्लाई करने के लिए है। वर्ष 2018 और 2019 में प्रमाणित बीजों की उपलब्धता क्रमशः 60 और 87.5 प्रतिशत बढ़ेगी। ■

सांस्कृतिक पुनरुत्थान

भारतीय जनसंघ का पहला राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन, कानपुर में 29 से 31 दिसंबर, 1952 को हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। इस अधिवेशन में कुल 15 प्रस्ताव पारित हुए। इनमें 7 **दीनदयाल उपाध्याय जी** ने प्रस्तुत किए, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का यह प्रस्ताव वैचारिक दृष्टि से बीजभूत प्रस्ताव है। इसी प्रस्ताव का विकास करते हुए दीनदयालजी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं एकात्म मानववाद अवधारणाओं को देश के समक्ष प्रस्तुत किया।

जनसंघ का मत है कि भारत तथा अन्य देशों के इतिहास पर विचार करने से यह सिद्ध होता है कि केवल भौगोलिक एकता एक राष्ट्रीयता के लिए पर्याप्त नहीं। एक देश के निवासी जन एक राष्ट्र तभी बनाते हैं, जब वे एक संस्कृति के द्वारा एकरूप कर दिए गए हों। जब तक भारतीय समाज एक संस्कृति का अनुगामी रहा, तब तक अनेक राज्य रहते हुए भी यहां के जनों की मूलभूत एक राष्ट्रीयता बनी रही, परंतु जब से विदेशी शासकों ने अपने लाभ के लिए एकात्मता को भंग कर विदेशपरक संस्कृतियों को इस देश में जन्म दिया है, तब से भारत की एक राष्ट्रीयता संकटापन्न हो गई। अनेक शताब्दियों तक एक राष्ट्र का घोष करते हुए भी भारत में मुसलिम संप्रदायवादियों के द्विराष्ट्रवाद की विजय हुई, देश विभक्त हुआ और पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों के लिए रहना असंभव कर दिया गया। दूसरी ओर भारत में मुस्लिम संस्कृति को अलग मान उसकी रक्षा और संबर्धन के ब्याज से उसी द्विराष्ट्र वाली प्रवृत्ति का पोषण हो रहा है, जो राष्ट्र-निर्माण के मार्ग में बाधक है।

अतः जनसंघ निर्णय करता है कि भारत की एक राष्ट्रीयता के विकास और दृष्टिकोण हेतु यह नितांत आवश्यक है कि भारत में एक संस्कृति का पोषण हो और समाज के सभी घटकों में चाहे वह किसी धर्म के मानने अथवा किसी भी प्रदेश के निवासी हों, उसका प्रचार किया जाए और उसे मान्यता दिलाई जाए।

इस कार्य के संपादन के लिए निम्नलिखित दिशाओं में समाज और शासन को अग्रसर होना चाहिए-

1. शिक्षा को राष्ट्र संस्कृति पर आधारित किया जाना चाहिए। उपनिषद्, गीता, रामायण, महाभारत तथा अर्वाचीन-भारतीय भाषाओं द्वारा भारतीय संस्कृति को जीवित रखने वाले साहित्य सर्जकों से सबका परिचय कराया जाए और वह समय शीघ्र आए, जब सामाजिक जीवन के सभी केंद्रों में इस सांस्कृतिक धारा को अनिवार्य समझा जाए।
2. भारत के राष्ट्रपुरुषों के जन्मदिवस आदि राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाएं, जिनमें शासन प्रेरणा, प्रबंध और धन का सहायक हो और राष्ट्र के सभी नागरिक भाग लें।
3. भारत के प्रधान त्योहारों को राष्ट्रीय त्योहारों के रूप में मनाया जाए। इसमें होली, विजयादशमी, रक्षाबंधन तथा दीपावली का समावेश हो।
4. भारत के सामाजिक जीवन के सभी अंगों में क्षेत्रीय भाषा अथवा राष्ट्रभाषा का प्रचलन करने के लिए शासन और समाज की ओर से समर्थ तथा सतत उद्योग प्रारंभ हो, जिससे भारतीय समाज अपना विकास राष्ट्रीय आधारों पर कर सके।
5. संस्कृत भाषा पुनरुज्जीवन किया जाए, उसका ज्ञान विद्वत्ता के लिए अनिवार्य हो तथा उद्योग किया जाए कि देश की समस्त भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि को ही एक लिपि के रूप में स्वीकार किया जाए।
6. भारतीय इतिहास शुद्ध रूप से भारतीय जन का इतिहास हो। इसमें विदेशी शासकों के नाम पर काल विभाजन न होकर भारतीय समाज के विकास, उसमें होने वाले आंदोलनों और क्रांतियों के आधार पर काल विभाजन कल्पित हो तथा भारतीय संस्कृति तथा भारतीय संस्कृति के पूर्वकालीन विश्वव्यापी प्रसार की गाथा भी सम्मिलित हो।
7. संस्कृति के पुनरुत्थान तथा एकीकरण की दृष्टि से यह संघ देश के हिंदू समाज को सचेत करता है कि अपनी इतिहाससिद्ध अंतरंग सामाजिक दुर्बलताओं का शीघ्रता से निराकरण करें। विशेषकर जातिभेद के कारण उत्पन्न, ऊंच-नीच और विभिन्नताओं को तत्काल दूर किया जाए और पिछड़े हुए वर्गों तथा अन्य हिंदुओं के बीच पूर्ण साम्य की स्थापना की जाए। साथी समाज के हेतु धार्मिक पर्वों और उत्सवों को सामूहिक, संगठित तथा अनुशासित रूप में मनाया जाए और समाज के जनों का उसमें सहयोग प्राप्त किया जाए।
8. इस प्रकार अपने अंतरंग सुधार के साथ-साथ हिंदू समाज का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है कि भारतीय जन के उन भागों के राष्ट्रीयकरण का महान् कार्य हाथ में ले, जो विदेशियों द्वारा स्वदेशपराङ्मुख और विदेशाभिमुख बना दिए गए हैं। हिंदू समाज को चाहिए, उन्हें आत्मसात् कर ले। केवल इसी प्रकार सांप्रदायिकता का अंत हो सकता है और राष्ट्र की एकनिष्ठता तथा दृढ़ता निष्पन्न हो सकती है। ■

- पांचजन्य, दिसंबर 31, 1952

कुशाभाऊ ठाकरे

(15 अगस्त 1922 - 28 दिसंबर 2003)

शत-शत नमन!

श्री कुशाभाऊ ठाकरे नैतिकता, आदर्श व सिद्धांतों के प्रकाश स्तंभ थे। वे निष्काम कर्मयोगी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद को मजबूत बनाने में उनका योगदान अमूल्य है। वे जीवनपर्यंत बेदाग रहे। श्री ठाकरे भाजपा के उन नेताओं में से थे, जिन्होंने साइकिल चलाकर और चने खाकर पार्टी का काम किया। यही कारण है कि पार्टी में उनका व्यापक प्रभाव था। श्री कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म 15 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश स्थित धार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदर राव श्रीपति राव ठाकरे और माता का नाम शांता भाई सुंदर राव ठाकरे था। इनकी शिक्षा धार और ग्वालियर में हुई थी। 1942 में संघ का प्रचारक बनने के बाद उन्होंने मध्यप्रदेश के कोने-कोने में निष्ठावान स्वयंसेवकों की सेना खड़ी की। वे कुशल संगठनकर्ता थे। श्री कुशाभाऊ ठाकरे संघ में काम की शुरुआत उस समय की थी, जब इस संगठन का विस्तार व्यापक नहीं था। सच तो यह है कि किसी विचारधारा और लक्ष्य के प्रति उनके समान निष्ठा विरले लोगों में देखी जाती है। उनके सार्वजनिक जीवन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। वे प्रारंभ में केवल संघ के काम से जुड़े रहे। जनसंघ (अब भाजपा) की स्थापना के बाद उनका संबंध राजनैतिक गतिविधियों से हुआ। उन्होंने अपने-आपको संगठन तक सीमित रखा और संगठन को और मजबूत बनाने के लिए सदैव कार्य करते रहे।

श्री कुशाभाऊ ठाकरे 1956 में मध्य प्रदेश सचिव (संगठन) बने। वे 1967 में भारतीय जन संघ के अखिल भारतीय सचिव बने। आपातकाल के दौरान वे 19 महीने जेल में रहे। 1980 में भाजपा के अखिल भारतीय सचिव बनाए गए। 1986 से 1991 तक वे अखिल भारतीय महासचिव व मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे। 1998 में वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इस पद वे 2000 तक रहे। 28 दिसंबर 2003 को उनका देहांत हो गया।

राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण अटूट था। इंदौर में एक सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि सामने वाले के पास परमाणु बम है, तो हमारा सिपाही तमंचे से नहीं लड़ेगा। हमने अपनी सेना को आधुनिक और आणविक क्षमता से लैस करना जरूरी समझा। हमें पता था कि ऐसा करने पर हमें कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उनको लगता है कि ऐसा करने से भारत डूब जाएगा, पर भारत हमेशा ही अपने पैरों

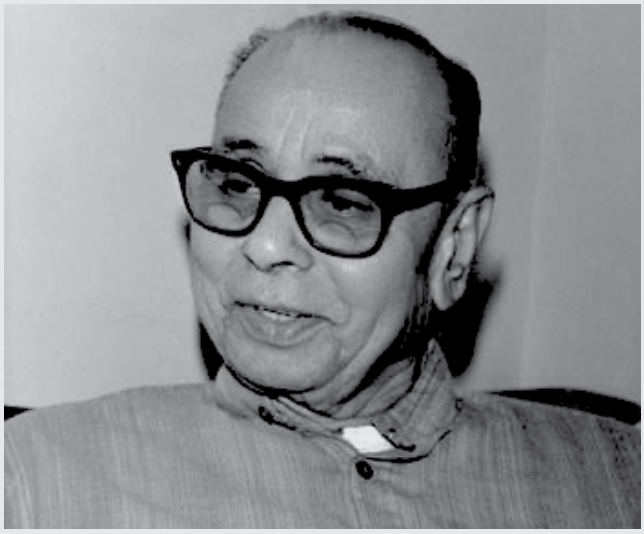

पर खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। देश के विकास में लगे 80 प्रतिशत साधन स्वदेशी हैं। विदेशी मदद तो मात्र 15-20 प्रतिशत है। हम सूखी रोटी खा लेंगे, पर पश्चिमी देशों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। श्री ठाकरे स्वाभिमान पर समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसलिए वे राष्ट्र का मजबूत और शक्तिशाली देखना चाहते थे।

श्री कुशाभाऊ ठाकरे का मानना था कि किसी राजनैतिक संगठन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग की सुख-समृद्धि सुनिश्चित करना है। 7 फरवरी 1999 को भोपाल में श्री ठाकरे ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक सफलता पाना नहीं है। पार्टी का मकसद है कि समाज के सभी वर्गों में सुख और समृद्धि आए। आज जोड़-तोड़ और वर्गों में दरार चौड़ी करके राजनीतिक कामयाबी तो हासिल की जाती है, पर लोगों के दिलों में घर नहीं बनाया जा सकता। भाजपा वे रास्ते कभी नहीं अपनाएगी जो दूसरे दल अपनाते हैं।

श्री कुशाभाऊ ठाकरे जीवन पर्यंत संगठन के लिए कार्य करते रहे। कार्यकर्ताओं से उनका संबंध अटूट था। 19 अप्रैल 1996 को भोपाल में उन्होंने कहा था कि हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं। जनता ने हम पर चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। जनता को वर्तमान सरकार से बहुत आशा है। ऐसे समय में भाजपा कार्यकर्ताओं का दायित्व बढ़ गया है और हमें अपना दायित्व समझना होगा। ■

राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति पर चिंतन

अरुण जेटली

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी कुछ घंटों में पद से मुक्त हो रहे हैं। उनका राष्ट्रपति पद पर पहुंचना एक राजनेता के जीवन का सर्वोच्च बिंदु है। भारत ने उनके जैसे सिर्फ कुछ नेता देखे हैं, जिनमें यह क्षमता थी कि अपने राजनैतिक दल के प्रति प्रतिबद्धता और विभिन्न पदों पर बैठने के बावजूद एक 'स्टेट्समैन' के रूप में उभरे। प्रणब दा ऐसे कुछ नेताओं में से हैं, जो जिन पदों पर बैठे उन्हें सुशोभित किया।

मेरा उनसे पहला संपर्क उस समय हुआ जब वाजपेयी सरकार के समय वे डॉ. मनमोहन सिंह के साथ विपक्ष की भूमिका में थे। वे महत्वपूर्ण स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे, जिसने कई कानूनों को पारित करने की जिम्मेदारी निभाई। उनमें से तीन महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे। पहला, उस कानून से संबंधित था जिसने कई राज्यों में आबादी में परिवर्तन के बावजूद राज्य विधान सभाओं और लोकसभा की सीटों को अपरिवर्तित करने से था। दूसरा, दल–बदल विरोधी कानून से था और तीसरे का संबंध केंद्र और राज्यों की मंत्रीपरिषद् के आकार को सीमित करने से था। उनकी समिति ने सरकार द्वारा निर्मित प्रारूप में सुधार कर इन संशोधनों पर शीघ्रता से विचार किया। उन्होंने इन मुद्दों पर आम सहमति बनाई। विपक्ष में रहने के बावजूद वे कभी भी बाधा नहीं बने। वे संसदीय प्रणाली की उपज थे और वृहद राष्ट्र हितों के लिए संसद का उपयोग किया।

उनके बाद के वर्षों में सांसद और बाद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैंने बहुत ही गहराई से उनका अवलोकन किया। उनकी यह नैसर्गिक प्रतिभा थी कि वे दलगत वाद–विवाद से ऊपर रहते थे। संसद में वे सदैव एमिकस करिय (न्याय की मदद करने वाला) के रूप में बहस करते थे। वे सदन के मित्र थे, न कि एक दल के नेता। उनकी यह योग्यता उनके विचारों के प्रति आम सहमति बनाने में मदद करती थी। वह शायद ही कभी क्रोधित होते थे और कभी होते भी थे, तो अगले क्षण मुस्कराकर उसकी भरपाई भी कर देते थे।

उनके पास गहरा इतिहासबोध था, जिसमें संवैधानिक औचित्यता की दृष्टि मिली हुई थी। उनके अंदर का लोकतंत्रवादी सरकार और विपक्ष को मुख्य मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता था। किस उपयुक्त रास्ते का चयन करना है, इसके लिए वे संसदीय

और न्यायिक उद्धरणों का हवाला देते थे।

राष्ट्रपति के रूप में, वह निर्विवाद रूप से संविधान के अभिभावक थे। उन्हें एहसास था कि लोकतंत्र में केवल एक शक्ति केंद्र हो

प्रणब दा में एक अनोखा आकर्षण रहा, जिसके चलते उन्हें कई प्रशंसक मिले। उनसे सभी वार्ताकार सहज रहे। उनका कद लगातार बढ़ता गया। एक वरिष्ठ मंत्री से राष्ट्रपति के रूप में उनका उत्तरदायित्व अनुकरणीय था। राष्ट्रपति के तौर पर वे पूरी तरह से गैर–पक्षपातपूर्ण थे और खुद को एक सलाहकार और अपनी सरकारों के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया।

सकता है, अर्थात् निर्वाचित सरकार और प्रधान मंत्री। इसलिए, वे अपने राष्ट्रपति पद के दौरान दो अलग–अलग सरकारों के साथ सक्रियतापूर्वक समान रूप से जुड़े रहे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मंत्रिपरिषद के सभी फैसले संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप होनी चाहिए। कुछ अवसरों पर, वे निर्णयों के अनुमोदन से पहले संतुष्ट होना चाहते थे। मुझे आम तौर पर उसके साथ बातचीत करने के लिए भेजा जाता था। वह हमेशा संवैधानिक आवश्यकताओं और निष्पक्षता हेतु तथ्यों के साथ अच्छी तरह तैयार रहते थे। मंत्री–परिषद द्वारा अनुमोदित सलाह को इन तथ्यों से संतुलित करना पड़ता था। यह नाजुक संतुलन उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में बनाए रखा। उन्होंने मंत्रिपरिषद की सलाह को हमेशा स्वीकार किया।

प्रणब दा में एक अनोखा आकर्षण रहा, जिसके चलते उन्हें कई प्रशंसक मिले। उनसे सभी वार्ताकार सहज रहे। उनका कद लगातार बढ़ता गया। एक वरिष्ठ मंत्री से राष्ट्रपति के रूप में उनका उत्तरदायित्व अनुकरणीय था। राष्ट्रपति के तौर पर वे पूरी तरह से गैर–पक्षपातपूर्ण थे और खुद को एक सलाहकार और अपनी सरकारों के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने सरकार के कार्यक्रमों का श्रीगणेश किया और उनके पैरोकार बन गए। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि उन्हें संसद के समक्ष वस्तु एवं सेवा कर हेतु संवैधानिक सुधार प्रस्तुत करने का विशेष दायित्व मिला। वह राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान संविधान संशोधन को स्वीकृति देना चाहते थे, जब उन्होंने ऐसा किया तो इससे उन्हें बहुत संतुष्टि मिली।

वह एक महान कद के साथ राष्ट्रपति भवन से दायित्वमुक्त हो रहे हैं। वह अब देश को सलाह देने और मार्गदर्शन करने की एक बड़ी भूमिका में रहेंगे, जिसमें वह हमेशा से रहे हैं। ■

(लेखक केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री हैं)

गरीब छात्रों के लिए योजना

केन्द्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। उच्च शिक्षा में गरीब छात्रों की पर्याप्त भागीदारी के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है।

केन्द्र सरकार की योजना के अंतर्गत कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के तहत मदद दी जा रही है। इसके तहत 6 लाख प्रतिवर्ष से कम आय वाले परिवार के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान दैनिक खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। किसी बोर्ड परीक्षा में 10+2 पैटर्न या इसके समकक्ष नियमित पाठ्यक्रम में सफल हुए छात्रों में से संबंधित संकाय में 80 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले ऐसे छात्र योजना के तहत पात्र है जिन्हें किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है।

यह जानकारी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. मेहेन्द्र नाथ पाण्डेय ने लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि 4.50 लाख रुपये से कम आय वाले माता-पिता के बच्चे को पढ़ाई के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इसके

तहत मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि और अतिरिक्त के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ■

क्या ममता की तृणमूल कांग्रेस तेजी से जिन्ना की मुस्लिम लीग बन रही है?

मीनाक्षी लेखी

जहां नरेंद्र मोदी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' की राजनीति कर रही है, वहीं ममता बनर्जी हिंदू उत्पीड़न की कश्मीर शैली को अपनाते हुए पश्चिम बंगाल को एक "मुस्लिम राज्य" घोषित करने के रास्ते पर चल रही हैं। जबसे वह सत्ता में आई हैं तब से बंगाल में हिंदू सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर जेहादियों का उत्पीड़न झेल रहे हैं। कई इलाकों में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सुनियोजित ढंग से हिंदुओं को निशाना बनाये जाने की घटनाओं ने पश्चिम बंगाल को 'हेट स्टेट ऑफ इंडिया' में बदल दिया है। चाहे मुसलमानों के मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन को स्थगित करना हो या बंगाल के स्कूलों में सरस्वती पूजा पर नबी-दिवस को प्राथमिकता देना हो, ममता सरकार बंगाल को तेजी से एक इस्लामिक राज्य में बदल रही है। बर्दवान विस्फोट, धुलागढ़ में हिंदुओं पर हमला, मालदा और हाल ही में बशीरहट में हिंदुओं पर हमलों से लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के द्वारा और मुसलमानों की सरकार है। जल्द ही अन्य सामाजिक समूहों को कश्मीर की तर्ज पर विलुप्त होने की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जून 2016 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इमामों और मुअज्ज़िनों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा घोषित भत्ते को असंवैधानिक और जनहित के खिलाफ करार देते हुए खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि यह भत्ता संविधान के अनुच्छेद 14 और 15/1 का उल्लंघन करता है, जिसके अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

अगर हम ममता के आचरण को गहराई से देखें तो उनके पाकिस्तान से सम्बन्ध साफ तौर पर उभर कर आते हैं। पाकिस्तान के एक दैनिक अख़बार 'द डॉन' में 29.04.2016 को ''कैनवासिंग इन 'मिनी पाकिस्तान' ऑफ कोलकाता'' कैप्शन के साथ छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी कैबिनेट में शहरी विकास और नगर निकाय मामलों के मंत्री बॉबी फ़िरहाद हाकिम ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ टहलते हुए गार्डन रीच को 'मिनी-पाकिस्तान' कहकर सम्बोधित किया था। पाकिस्तानी अखबार 'द डॉन' की पत्रकार मलीहा हामिद सिद्दीकी के अनुसार बॉबी फ़िरहाद हाकिम ने उनसे कहा था कि ''आइये हम आपको कोलकाता में मिनी पकिस्तान लेकर चलते हैं।" डॉन की रिपोर्टर ने आगे लिखा, "मुझे हाथ में नोटबुक लेकर घूमते हुए देखकर आस-पास के लोग जानना चाहते थे कि मैं किस टीवी चैनल के लिए काम करती हूं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तान से हूं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अपने रिश्तेदारों के बारे में बताया जो पाकिस्तान में रहते हैं।" हाकिम को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफी करीबी माना जाता है और वह तृणमूल कांग्रेस की राज्य में बड़े पैमाने पर मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम गुंडाराज को अनुमति देते हुए मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख मुस्लिम चेहरा है।

एक दिन बाद संघ के समर्थन से 200 से ज्यादा श्रीराम शोभायात्रा पूरे पश्चिम बंगाम सहित कोलकाता के अलग-अलग हिस्सों में निकाली गई। शोभा यात्रा में हर वर्ग के लोगों ने धर्मग्रंथों में उल्लिखित पारंपरिक हथियार जैसे तलवार, भाला, गदा, धनुष और तीर से सुसज्जित होकर बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। जिसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा, 'जिन लोगों ने इसका आयोजन किया है उन्होंने बंगाल की संस्कृति, हिंदू परंपरा और राज्य की कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया है।' मुख्यमंत्री के इस बयान के कुछ समय बाद ही पश्चिमी मिदनापुर की पुलिस ने विधायक और भाजपा के राज्य प्रमुख दिलीप घोष के खिलाफ 1959 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, क्योंकि खड़गपुर में राम नवमी (5 अप्रैल 2017) के दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तलवार के साथ देखे गए थे, लेकिन राज्य में मुसलमानों के लिए दूसरे मापदंड है। मुस्लिम समुदाय के लोग धार्मिक त्यौहारों और कार्यक्रमों का आयोजन बिना किसी इजाजत के भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के इसी तरह के आयोजनों के लिए अक्सर हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ता है क्योंकि राज्य पुलिस इनके आयोजनों की इजाजत नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय मुहर्रम के जुलूसों के दौरान तलवार और अन्य हथियारों का प्रदर्शन खुलेआम बिना किसी

प्रतिबंध के करते हैं, लेकिन रामनवमी के आयोजकों को इसी तरह के आयोजनों के लिए पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। ममता बनर्जी मुस्लिम धर्मगुरूओं और मुअज़्ज़िन्स के साथ अपने भाईयों की तरह व्यवहार करते हुए उनको भत्ते तक प्रदान करती है। वहीं हिंदू धर्मगुरूओं से भाईयों की जगह दुश्मनों की तरह व्यवहार किया जाता है। साथ ही, हिंदू धर्मगुरूओं के इस तरह की मांग पर उन्हें बुरा अंजाम भुगतने तक की धमकी दी जाती है। बंगाल में हिंदुओं और मुसलमान के बीच भेदभाव असीम स्तर पर है।

एक तरफ बंगाल सरकार राज्य में कुरान और उर्दू पर आधारित मदरसा शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठनों और संघ से जुड़े विद्यालयों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। बंगाल सरकार ने राष्ट्रवादी ट्रस्टों द्वारा संचालित 125 विद्यालयों को नोटिस में लिया है। राज्य में इन राष्ट्रवादी ट्रस्टों के 350 से सभी अधिक विद्यालय हैं जिनमें 60 हजार से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। यह आंकड़े भी बहुत रोचक हैं कि बंगाल सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा के लिए 2815 करोड़ का एक बड़ा बजट निर्धारित किया है। यह बजट सिंचाई और जलमार्ग के बजट (2410 करोड़ रूपये), बड़े उद्योगों-वस्त्र उद्योग (2154 करोड़ रूपये) और अन्य पिछड़ा और आदिवासी कल्याण विभाग के लिए लिए जारी किए गए बजट (2775 करोड़ रूपये) की तुलना में अधिक है।

बंगाल हमेशा गवाह रहा है कि कुछ संगठनों ने मिलकर राज्य में एंटी-हिंदू नीतियों को बढ़ावा दिया है, जो कि राज्य की कई राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा से मेल खाती है। उदाहरण के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने लंबे समय तक अपनी एंटी-हिंदू विचारधारा का इस्तेमाल गैर-हिंदू बहुल संसदीय क्षेत्रों में सत्ता प्राप्ति के लिए करती रही है। विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को बंगाल में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किया गया। 1951 में राज्य की हिंदू जनसंख्या 78.45 प्रतिशत थी जो आश्चर्यजनक रूप से गिरकर 2011 की जनगणना में 70.54 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

इसलिए यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि भाजपा की धर्मनिरपेक्ष छवि अन्य राजनीतिक दलों में बैचेनी का कारण बन रही है। बंगाल में भाजपा का उदय ममता बनर्जी की सांप्रदायिक राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भाजपा के बढ़ते जनाधार के कारण ममता बनर्जी इतनी डरी हुई है कि उन्होंने हाल ही में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं रूपा गांगुली और कैलाश विजयवर्गीय को फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी गई जो कि भाजपा के बढ़ते प्रभाव को दबाने की कोशिश है।

सभी मामलों के केंद्र में राज्य की 30 प्रतिशत मुस्लिम वोट बैंक है, जिनमें अधिकतर अवैध रूप से बांग्लादेश से आए आप्रवासी नागरिक है। जिन्हें पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने वैधता दी अब यही काम ममता बनर्जी कर रही है। 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी नागरिकों में से 1.5 करोड़ मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता और मतदान का अधिकार दिया गया है। ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती है कि उनके द्वारा लाभान्वित 30 प्रतिशत काडर राज्य की सत्ता प्राप्ति के लिए काफी है। वास्तव में ममता की जीत के पीछे हमेशा मुसलमानों का जनसांख्यिकीय झुकाव है। राज्य में बड़ी संख्या में इमामों, मुल्लाओं और कट्टरपंथी ताकतों द्वारा मुस्लिम वोट बैंक को नियंत्रित किया जाता है जो छदम् रूप से सरकार में भागीदार होते हैं।

पश्चिम बंगाल में 2200 किलोमीटर की भारत-बांग्लादेश सीमा है जो हरकत-उल- जिहादी अल इस्लामी (हुजी) और जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के लिए भारत में घुसपैठ करने का सबसे उपयुक्त मार्ग है। हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 2010 हुजी और जेएमबी के आतंकियों ने तीन राज्यों के माध्यम से भारत में घुसपैठ किया है, इनमें से करीब 720 अकेले पश्चिम बंगाल के रास्ते से आए है। हालांकि बंगाल सरकार के अधिकारियों को इस रिपोर्ट पर संदेह है। इसके बावजूद कि 2014 और 2015 में क्रमशः 800 और 659 आतंकवादियों ने बंगाल के रास्ते से घुसपैठ की थी। वहीं ढाका गुलशन कैफे विस्फोट के मास्टमाइंड और कुख्यात आतंकी बंगाल के एक होटल में ठहरे थे। आतंकी घुसपैठ पर हमेशा ममता बनर्जी यह कहती है कि सीमाओं की सुरक्षा केंद्र के जिम्मे होती है। वहीं तथ्य यह है कि केंद्र पश्चिम बंगाल को संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैय्या करवा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सीमाएं आतंकवादियों और तस्करों के लिए सुगम रास्ता अभी भी बनी हुई हैं।

ममता बनर्जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। आरोप है कि 31 मार्च 2016 में विवेकानंद मार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाइओवर के गिरने के पीछे भी स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता का हाथ था। टीएमसी के नेता द्वारा फ्लाइओवर के निर्माण में दोयम दर्जे की निर्माण सामाग्रियों की आपूर्ति की गई थी, जिस कारण 27 लोगों को अपनी जिंदगियां गंवानी पड़ी थी। ममता बनर्जी के नेतृत्व के दौरान टीएमसी नेताओं के उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार का पर्याप्त सबूत शारदा चिट-फंड घोटाला, रोज वेली और नारदा स्टिंग के माध्यम से समझा जा सकता है।

6 जुलाई 2017 को बंगाल के जनक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 126वें जयंती पर राज्य इस बात का गवाह है कि जो डर 1946 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 'बंगाली हिंदू मातृभूमि आंदोलन' के दौरान महसूस किया था, जब ब्रिटिश संरक्षण में जिन्ना की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे (ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स) और नोआखली दंगों के दौरान 9000 हजार से अधिक हिंदुओं का नरसंहार किया था। हालांकि इतिहास खुद को दोहराता है, जिन्ना की मुस्लिम लीग की तरह ही ममता बनर्जी भी एक ऐसा माहौल बना रही है, जिसे बंगाल में हिंदूओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के रूप में याद रखा जाएगा। ■

(लेखिका भाजपा सांसद हैं)

जीएसटी सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन है

| गोपाल कृष्ण अग्रवाल |

जीएसटी के सम्बंध में लोगों की प्रारंभिक चिंता और आशंका बहुत हद तक अब समाप्त हो गई है। बची हुई कुछ आशंका कार्यान्वयन संबंधी है। लोगों को चिंता है कि कैसे उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, प्रोफिटिंयरिंग क्लास को लेकर गलतफहमी भी है। आशंका है कि कैसे घटे करों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना है। ये ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें सलाह मशविरा के माध्यम से हल करना है। मैं स्वयं भी कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रमों में जा रहा हूं। जीएसटी संबंधी जानकारी देने के लिए व्यापार संस्थाओं और उद्यमियों के साथ कई क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन हो रहा है।

जीएसटी मात्र आर्थिक सुधार नहीं है; अधिक पारदर्शी और कर-अनुपालक समाज के जरिए यह एक सामाजिक सुधार की प्रकिया है। उपभोक्ताओं के लिए इससे उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। सरकार के लिए इससे अधिक कर-संग्रह होगा। करों के समावेश और जीएसटी (जीएसटीएन) नेटवर्क के जरिए कहीं अधिक पारदर्शी और सरल व्यवस्था का निर्माण होगा।

विमुद्रीकरण के अनुभव से स्पष्ट होता है कि भारत में लोकप्रिय भावना एक पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और खुली अर्थव्यवस्था है। कर अदायगी की पारदर्शी व्यवस्था का विरोध कम होता जा रहा है।

संकल्पनात्मक रूप से किसी को भी जीएसटी से कोई समस्या नहीं है। इससे बहुआयामी करों में कमी आती है, (जिसमें 18 केन्द्रीय और राज्य कर समाहित हो जाते हैं), जिससे उपभोक्ताओं के लिए अप्रत्यक्ष कर कम हो जाते हैं। इससे ऑनलाइन रजिस्टेशन द्वारा व्यापार करना, रिटर्न और आकलन आसान हो जाता है। यह एकमात्र व्यवस्था है, जिससे हम एक कर, एक मार्केट स्थापित कर सकते हैं। इससे हमे एक ऑब्जेक्टिव, ऑनलाइन, पारदर्शी कर व्यवस्था प्राप्त होती है और हम सरकार अनुपालन पर भी नजर रख सकती हैं।

व्यापारियों के लिए, जिनका टर्न ओवर 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है, वे जीएसटी से बाहर हैं। जिन व्यापारियों और मैन्युफैक्चेरर का टर्न ओवर 20 लाख और 75 लाख के बीच है, उनके पास कम्पोजिट योजना का विकल्प है। उन्हें मात्र एक/दो प्रतिशत जीएसटी देना होगा पर उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उन्हें प्रत्येक 200 रुपए से कम के ट्रांजेक्शन के लिए अलग से चालान जारी नहीं करना होता है। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों को जीएसटी प्रणाली से निजात मिलता है।

जीएसटी में सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी विवरणों के साथ प्रारंभिक ट्रांजेक्शन, GST नेटवर्क पर डालना आवश्यक है और बाकी सभी विवरण अपने आप समाहित हो जाएंगे। सरकार एंटी-प्रोफिटियरिंग के जरिए उपभोक्ताओं को घटे कर दरों का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और इसके लिए अलग से अथारिटी है। यह एंटी-प्रोफिटियरिंग क्लास छोटे और मंझले व्यापारियों नहीं लागू किया जाएगा और दो साल में यह समाप्त भी हो जाएगी।

जो लोग इसका विरोध करते हैं, उन्हें इसकी पूरी जानकारी ठीक

प्रकार से नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सी अफवाहें और गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, मेरा निवेदन है कि वे इन पर ध्यान न दें और केवल विशेषज्ञों की सलाह पर काम करें। सरकार बहुत ही सक्रिय है और जीएसटी पर सतत काम चल रहा है। कोई विसंगति मिलती है, तो उसे ठीक करने पर उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है।

बहुत सी गलतफहमियां है। उदाहरणार्थ, कुछ लोग जीएसटी केवल सेल्स टेक्स से तुलना कर रहे हैं। बहुत से विरोध उन लोगों की तरफ से भी उभर कर आ रहे हैं जो देश को बेहतर कर अनुपालन की दिशा में बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के

साथ यह समस्या है कि व्यापारिक लेन-देन का बहुत बड़ा हिस्सा कर व्यवस्था से बाहर है। इसी के परिणामस्वरूप देश की 58 प्रतिशत संपत्ति केवल एक प्रतिशत लोगों के हाथों में सिमट गई है। भाजपा पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था के मार्ग पर चलना चाहती है। जीएसटी इस दिशा में एक बड़ा कदम है। मेरे विचार में बड़ी संख्या में लोग इसका समर्थन कर रहे है।

इसी प्रकार का समर्थन हमें 'विमुद्रीकरण' पर भी मिला था। लोगों ने हमारा समर्थन इसलिए किया था, क्योंकि वे जानते थे कि दो प्रकार की 'लीकेज' होती है, जिसमें एक कर संग्रह व्यवस्था में है और दूसरी सरकारी सहायता तंत्र में है। इसके कारण एक बड़ा भारी वर्ग गरीबी से उभर नही पा रहा, जबकि दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी इससे फल-फूल रहे हैं। हमने सरकारी सहायता व्यवस्था को सुचारू किया है। इसमें आधार व्यवस्था और मोबाइल्स (जेएएम) को जनधन अकाउंट से जोड़कर लाभार्थियों को सीधे लाभ पहुंचाना शुरू हो गया है। अब जीएसटी के माध्यम से यह व्यवस्था और सुदृढ होगी, जब सारा व्यापारिक लेन-देन औपचारिक व्यवस्था के माध्यम से होगा।

हमें विश्वास है कि आम लोग इसका समर्थन करेंगे। हमारे पास 'माइग्रेशन' अवधि है जिसमें नई कर व्यवस्था को समझने का पूरा समय है। इससे प्रारम्भिक सभी आशंकाएं समाप्त हो जाएंगी। हम आम लोगों की सभी समस्याओं के प्रति संवेदनशील और सजग हैं। इसी लिए सरकार ने अभी टीडीएस से कर कटौती का कार्यान्वयन रोक दिया है, जिससे जटिलताएं पैदा हो रही थीं। सरकार ने एमआरपी पर भी स्पष्टीकरण दिया है कि पुरानी और नई दोनों कीमत समान पर छापनी होगी, ताकि उपभोक्ताओं को पता चल जाए की जीएसटी का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा है और घटे कर दरों का उसको लाभ मिला है कि नहीं। अब सामान की बुनियादी कीमत बहुत हद तक नियंत्रित भी की जा सकेगी। ■

हमारी अर्थव्यवस्था के साथ यह समस्या है कि व्यापारिक लेन-देन का बहुत बड़ा हिस्सा कर व्यवस्था से बाहर है। इसी के परिणामस्वरूप देश की 58 प्रतिशत संपत्ति केवल एक प्रतिशत लोगों के हाथों में सिमट गई है। भाजपा पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था के मार्ग पर चलना चाहती है। जीएसटी इस दिशा में एक बड़ा कदम है। मेरे विचार में बड़ी संख्या में लोग इसका समर्थन कर रहे है।

(लेखक भाजपा के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

महिला यात्रियों की हिफाजत और सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे की ओर से उठाए गए कदम

रेल राज्य मंत्री श्री राजेन गोहिन द्वारा राज्य सभा में 28 जुलाई को दी गई जानकारी के अनुसार रेलगाड़ियों में यात्रियों सहित महिला यात्रियों की हिफाजत और सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं:

- असुरक्षित और चिन्हित मार्गों/खंडों पर 2500 रेलगाड़ियों (औसतन) को प्रतिदिन रेलवे संरक्षण बल द्वारा मार्ग में सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में प्रतिदिन 2200 ट्रेनों को जीआरपी द्वारा मार्ग में सुरक्षा दी जाती है।
- मुसीबत में फंसे यात्रियों की सहायता के लिए भारतीय रेलवे में सुरक्षा हेल्पलाइन नम्बर 182 शुरू किया गया है।
- रेलगाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले दस्तों को मार्ग और स्टेशनों पर गाड़ी रूकने के समय महिलाओं के डिब्बों में अतिरिक्त चौकसी बरतने को कहा गया है।
- महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरूषों का प्रवेश रोकने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाए जाते हैं और यदि कोई पुरूष ऐसा करता पाया जाता है, तो रेलवे कानून के प्रावधानों के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
- यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे के लगभग 344 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाती है।
- महानगरों में चलाई जाने वाली महिला स्पेशल रेलगाड़ियों को महिला आरपीएफ कांस्टेबलों द्वारा मार्ग में सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।
- महानगरों में चलाई जाने वाली उपनगरीय रेलगाड़ियों को आरपीएफ और जीआरपी द्वारा मार्ग में सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देर रात और सुबह-सवेरे सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाती है।
- आरपीएफ, जीआरपी द्वारा अपराध का उचित पंजीकरण और जांच-पड़ताल सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस के साथ सभी स्तरों पर नियमित रूप से समन्वय बैठकें करता है। ■

प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक इजराइल यात्रा

भारत-इजराइल के बीच 7 अहम समझौते

कृषि, स्पेस और गंगा की सफाई प्रमुख

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4-6 जुलाई के दौरान इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा की। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली इजराइल यात्रा है। इस यात्रा के दौरान भारत और इजरायल के बीच अंतरिक्ष, कृषि और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सात महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि इस वर्ष भारत और इस्राइल ने अपने राजनयिक संबंधों के 25 साल पूरे किए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ऐतिहासिक इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 5 जुलाई को अंतरिक्ष, कृषि और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और इजराइल ने चार करोड़ डॉलर के भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवोन्मेषण कोष की स्थापना के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसके आलावा भारत में जल संरक्षण, भारत में राज्य स्तर पर जल उपयोगिता सुधार, भारत-इजराइल विकास सहयोग के तहत तीन (2018 से 2022) साल के लिए भारत में कृषि से जुड़े कार्य, परमाणु घड़ियों के निमार्ण सहयोग, जियो-लियो (Geo-Leo) ऑप्टिकल लिंक तथा छोटे उपग्रहों के निर्माण के लिए बिजली संचालन शक्ति को लेकर दोनों देशों की स्पेस एजियों के बीच करार हुए।

'आपका स्वागत है मेरे दोस्त': बेंजामिन नेतन्याहू

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को इजराइल पहुंचे। इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर एक भव्य स्वागत समारोह में उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिंदी में 'आपका स्वागत है मेरे दोस्त' कहते हुए अपने प्रेस वक्तव्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का खुली बाहों से स्वागत किया गया है और यहां तक कि आकाश भी दोनों देशों के बीच सहयोग की सीमा नहीं है। उन्होंने एक महान नेता और एक 'विश्व नेता' के रूप में प्रधानमंत्री की सराहना की।

इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने हिब्रू में शुभकामनाएं 'शालोम लेकुलम' देते हुए शुरुआत की। उन्होंने हिब्रू में यह भी कहा

कि 'यहां इजराइल आकर मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है।' उन्होंने ठीक 41 साल पहले 4 जुलाई को एंटेबे में इजराइली ऑपरेशन को याद किया जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बड़े भाई ने कई इजराइल बंधकों को बचाते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि निरंतर उच्च वृद्धि और समग्र विकास की हमारी राह में भारत इजराइल को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है।

उन्होंने कहा कि साझा आर्थिक समृद्धि के लिए साझेदारी करने के साथ-साथ हम आतंकवाद जैसे साझा खतरों से अपने समाज को सुरक्षित करने के लिए भी सहयोग कर रहे हैं।

हमारी मित्रता और गहरा करने का अवसर: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 जुलाई को एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि इस अदभुत यात्रा के दौरान मैं इजराइल आकर गौरवान्वित हुआ हूं। हालांकि, आधुनिक यात्रा में हमारे मार्ग अलग-अलग रहे हों, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक प्रगति में हमारा विश्वास एक जैसा ही रहा है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा एक अवसर हैः हमारी मित्रता की जड़ों को और गहरा करने के लिए; हमारे संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए और हमारे सहयोग के नए आयामों की दिशा में एक साथ आगे बढ़ने के लिए।

श्री मोदी ने कहा कि इजराइल उन प्रमुख देशों में शुमार है, जिनके पास इनोवेशन, जल और कृषि प्रौद्योगिकी में काफी विशेषज्ञता प्राप्त है। भारत के विकास में ये क्षेत्र मेरे प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। हमने इस बात पर सहमति जताई है कि जल दक्षता तथा संसाधन उपयोग; जल संरक्षण और इसका परिष्करण; कृषि में उत्पादकता में वृद्धि हमारे द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान करने की दिशा में प्रमुख क्षेत्र हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दोनों देशों की एक ही सोच है कि हमारे वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता एक साथ मिलकर उपरोक्त क्षेत्रों में दोनों देशों के हित में सोल्यूशन विकसित, निर्मित और कार्यान्वित करेंगे।

इजराइल में सामुदायिक रिसेप्शन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 जुलाई को कहा कि 70 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का आना ये अपने आप में एक खुशी का भी अवसर है और कुछ सवालिया निशान भी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मानव प्रकृति है कि जब आप किसी बहुत करीबी व्यक्ति से बहुत दिन बाद मिलते हैं, तो पहला रिएक्शन होता है बहुत दिन हुए मुलाकात और फिर कहते हैं ठीक हो कैसे हो और ये जो कैसे हो, ये पहला वाक्य ही एक प्रकार से कन्फेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। व्यक्ति का हाल-चाल पूछने के साथ-साथ तुरंत ये भी स्वीकार कर लेता है कि बहुत दिन बाद मिले हैं। मैं आपसे मेरी बात की शुरूआत इसी कन्फेशन से करना चाहता हूं वाकई बहुत दिन बाद मिले हैं और दिन भी कहना ठीक नहीं है सच ये है कि मिलने में कई साल लग गए 10, 20, 50 नहीं 70 साल लग गए।

उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 70 साल बाद भारत का

कोई प्रधानमंत्री आज इजराइल की धरती पर आप सबसे आशीर्वाद ले रहा है। इस अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री मेरे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू यहां उपस्थित हैं। इजराइल आने के बाद जिस तरह वो मेरे साथ रहें हैं, जैसा सम्मान उन्होंने दिया है वो भारत के सवा सौ करोड़ लोगों का सम्मान है। ऐसे सम्मान को, ऐसे प्यार को, ऐसे अपनेपन को कभी भी दुनिया में कोई भुला सकता है?

प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिया उपहार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू को केरल से पुरावशेष के दो सेट की प्रतिकृतियां उपहार स्वरूप भेंट की, जिन्हें भारत में यहूदियों के लंबे इतिहास में प्रमुख कलाकृतियों के तौर पर जाना जाता है। इनमें तांबे के प्लेटों के दो अलग-अलग सेट शामिल हैं। समझा जाता है कि इन पर 9-10वीं शताब्दी सी. ई. में लिखा गया होगा।

तांबे के प्लेटों का पहला सेट भारत में कोचीन यहूदियों के लिए एक महत्वपूर्ण पुरावशेष है। इसे हिंदू राजा चेरामन पेरुमल (भास्कर रवि वर्मा के रूप में चर्चित) द्वारा यहूदी नेता जोसेफ रब्बन को दिए गए वंशानुगत शाही विशेषाधिकारों और सुविधाओं का वर्णन करने वाला चार्टर माना जाता है। यहूदियों के पारंपरिक विवरणों के अनुसार, जोसेफ रब्बन को बाद में शिंघली के राजकुमार के रूप में ताज पहनाया गया था। सिंघली उस समय क्रांगानोर के समकक्ष एक स्थान था।

क्रांगानोर वही जगह है जहां यहूदियों ने कोच्चि एवं मालाबार में अन्य जगहों की ओर कूच करने से पहले सदियों तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वायत्तता का आनंद उठाया था। स्थानीय यहूदियों ने एक बार शिंघली/क्रांगानोर की एक मुट्ठी मिट्टी हरेक ताबूत में डाल दिया था, क्योंकि उसे एक पवित्र स्थान और 'दूसरा यरूशलेम' के रूप में माना जाता है। इन प्लेटों की प्रतिकृति को कोच्चि के मट्टानचेरी में परदेशी सिनेगॉग के सहयोग से तैयार किया गया है।

तांबे की प्लेटों का दूसरा सेट भारत के साथ यहूदी व्यापार के इतिहास का सबसे प्राचीन दस्तावेज माना जाता है। इन प्लेटों में स्थानीय हिंदू शासक द्वारा भूमि आवंटन एवं कर विशेषाधिकार अनुदान का वर्णन एक चर्च से किया है। साथ ही इसमें पश्चिम एशियाई एवं भारतीय व्यापारिक संगठनों को कोल्लम में व्यापार की निगरानी का भी वर्णन किया गया है। पश्चिमी एशियाई संगठनों में मुस्लिम, ईसाई, जोरोऑट्रियंस आदि शामिल हैं। साथ ही इसमें यहूदियों के एक समूह को भी शामिल किया गया है जिसने जुडियो-फारसी और संभवतः अरबी एवं पहलवी (मध्य फारसी) में भी में हस्ताक्षर किए थे। ऐसा लगता है कि इन प्लेटों पर उनके हस्ताक्षर उकेरे गए हैं, जिन्हें उस लिपि से अपरिचित किसी स्थानीय कामगार द्वारा काटा गया होगा। इन प्लेटों की प्रतिकृति को तैयार करने में केरल के तिरुवल्ला स्थित मालंकरा मार थोमा सीरियन चर्च के सहयोग उल्लेखनीय रहा।

साथ ही प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री को एक टोरा स्क्रॉल भी भेंट किया, जिसे केरल के परदेसी यहूदी समुदाय ने दान दिया था। करीब सौ साल पहले हस्तलिखित यह स्क्रॉल कोच्चि के परदेसी सिनेगॉग को समर्पित किया गया था, जिसे 1568 में बनाया गया था। टोरा लकड़ी के एक बक्से में लकड़ी के दांतों से घिरा है जो चांदी की चादर से ढंका हुआ है और धातु का मुकुट पुष्प आभूषण की तरह सोने की चादरों से ढंका है।

भारत और इजराइल के संबंध कई शताब्दियों से हैं: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 जुलाई को भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते 25 साल पुराने ही हों, लेकिन भारत और इजराइल के संबंध कई शताब्दियों से हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें बताया गया है, 13वीं शताब्दी में भारतीय सूफी संत बाबा फरीद यरुशलम आए थे और उन्होंने यहां एक गुफा में साधना की थी।

प्रधानमंत्री ने भारत और इजराइल के बीच पारंपरिक, सांस्कृतिक, विश्वास और मित्रतापूर्ण संबंधों का वर्णन किया। उन्होंने भारत और इजराइल के त्योहारों में समानता का भी जिक्र किया। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने होली और पुरिम, दीवाली और हनुका का उदाहरण दिया।

प्रधानमंत्री ने इजराइल द्वारा की गई शानदार तकनीकी प्रगति और उसकी लंबी बहादुरी एवं शहादत की परंपरा का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने पहले विश्व युद्ध के दौरान हैफा की आजादी में भारतीय सैनिकों द्वारा निभाई गई भूमिका को याद किया। उन्होंने भारतीय यहूदी समुदाय के भारत और इजराइल दोनों के लिए किए गए योगदान का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने इजराइल की नवाचार की भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि इजराइल ने जियो-थर्मल पावर, सौर पैनल, एग्रो-बायोटेक्नॉलाजी और सुरक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में भारत में किए गए सुधारों का भी जिक्र किया। उन्होंने जीएसटी लागू करने, प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी, बीमा एवं बैंकिंग क्षेत्र के सुधार और कौशल विकास समेत कई पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में दूसरी हरित क्रांति के लिए इजराइल के साथ साझेदारी काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान भविष्य में भारत और इजराइल के संबंधों का आधार बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में सुरक्षित बचे बच्चे मोशे होल्तजबर्ग से हुई मुलाकात को भी याद किया।

उन्होंने इजराइल में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया कि इजराइल में अनिवार्य सैन्य सेवा करने के बावजूद उन्हें ओसीआई कार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कहा कि इजराइल में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्हें यह भी घोषणा की कि जल्द ही दिल्ली, मुंबई और तेल अवीव के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी। ■

बिहार में फिर राजग सरकार

नीतीश कुमार बने मुख्यमंत्री, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री

बिहार में फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। गत 27 जुलाई को श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की छठी बार शपथ ली। राजभवन के राजेंद्र मंडपम में आयोजित समारोह में राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी ने श्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद मंत्री के रूप में एकमात्र श्री सुशील कुमार मोदी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनिल जैन, बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय, बिहार प्रदेश जदयू अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह के अलावा राजग के कई वरिष्ठ नेता, सांसद एवं विधायक उपस्थित थे।

इसके पश्चात् गत 28 जुलाई को राज्य में बनी जनता दल(यू) और भाजपा की साझा सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। 243 सदस्यों की विधानसभा में राजग सरकार के पक्ष में 131 और विरोध में 108 वोट पड़े। विदित हो कि जदयू की पूर्व सहयोगी पार्टी राजद के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर लग रहे भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जबर्दस्त अभियान चला रही है।

पूर्व महागठबंधन के शासन में उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिस पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने श्री यादव से स्पष्टीकरण की मांग की थी। लेकिन जवाब नहीं मिलने पर 26 जुलाई को श्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी को सौंप दिया।

> भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार को बधाई। सवा सौ करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। देश के, विशेष रूप से बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना आज देश और समय की मांग है।
>
> – नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

> बिहार के विकास और प्रगति के लिए भ्रष्टाचार के विरूद्ध आवाज उठाकर प्रदेश में पुनः सुशासन स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी को हार्दिक बधाई! मुझे विश्वास है कि बिहार सरकार और केंद्र की मोदी सरकार मिलकर बिहार में विकास के नए मापदंड स्थापित करेंगी।
>
> – अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष

इसके बाद, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी को श्री नीतीश कुमार को समर्थन देने का पत्र सौंप दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा और जदयू विधायक दल की संयुक्त बैठक में श्री नीतीश कुमार को नया नेता भी चुन लिया गया। इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के विधायक भी शामिल हुए। ■

विद्युत उत्पादन की लागत घटाने के लिए मेरिट एप और ई-बिडिंग पोर्टल लांच

केन्द्रीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने बिजली की खरीद के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के चयन हेतु राज्यों को ई-बिडिंग सोल्यूशन मुहैया कराने के लिए 5 जुलाई को ई-बिडिंग पोर्टल और मेरिट एप (आय एवं पारदर्शिता के कायाकल्प के लिए बिजली का मेरिट ऑर्डर डिस्पैच) लांच किए। घरेलू कोयले के उपयोग से जुड़ी लचीलापन योजना के तहत इनके घरेलू कोयले के हस्तांतरण के जरिए यह संभव हो पाएगा। गौरतलब है कि ई-बिडिंग पोर्टल को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है, जिससे कि राज्यों को पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से संभावित आईपीपी से बिजली की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित करने में सहूलियत हो सके।

इस अवसर पर श्री गोयल ने मीडिया को बताया कि ये दोनों ही पहल 'स्पीड, स्किल एवं स्केल' के जरिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन' के विजन की दिशा में की गई हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि मेरिट एप एवं वेब पोर्टल से कोयले का इष्टतम उपयोग संभव हो पाएगा, जिससे अगले पांच वर्षों में उपभोक्ताओं को लगभग 20,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।

श्री गोयल ने कहा कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने और उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ हस्तांतरित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग 'काम करने वाली सरकार'के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री के 'नए भारत' के विजन के अनुरूप किफायती, गुणवत्तापूर्ण एवं 24x7 बिजली तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत ने बिजली की उपलब्धता के मामले में तेजी से पर्याप्तता हासिल की है। अब समय आ गया है कि बेशकीमती एवं दुर्लभ ऊर्जा संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केन्द्रित किया जाए, ताकि परिचालन में किफायत एवं दक्षता प्राप्त की जा सके।

राज्य/डिस्कॉम टैरिफ नीति, 2016 के तहत बिजली की खरीद के लिए मेरिट ऑर्डर का अनुसरण करेंगी और मेरिट ऑर्डर व्यवस्था में एकरूपता होनी चाहिए।

मेरिट एप के निम्नलिखित फायदे हैं:

- उपभोक्ता और सहभागी प्रशासन का सशक्तिकरण
- सीमांत परिवर्तनीय लागत एवं स्रोत वार बिजली की खरीद से संबंधित पारदर्शी सूचनाओं का प्रसार
- परिचालन में किफायत एवं दक्षता को बढ़ावा मिलता है
- उपक्रम के पोर्टफोलियो एवं इसकी जटिलता को समझने में मदद मिलती है
- विद्युत परिचालन लागत का अनुकूलन

घरेलू कोयले के उपयोग से जुड़ी लचीलापन योजना के तहत आईपीपी के ज्यादा दक्ष उत्पादन केन्द्रों को कोयले का हस्तांतरण किया जाता है, जिससे उत्पादन लागत घट जाती है और अंततः उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत कम हो जाती है। ■

'श्यामा प्रसाद मुखर्जी - हिज विजन ऑफ़ एजुकेशन' पुस्तक का लोकार्पण

डॉ. मुखर्जी का मानना था कि मूल संस्कृति से मेल खाती शिक्षा पद्धति होनी चाहिए: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 15 जुलाई को नई दिल्ली के नेहरू मेमोरियल में 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी-हिज विजन ऑफ़ एजुकेशन' पुस्तक का लोकार्पण किया। इस पुस्तक का संपादन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान के निदेशक श्री अनिर्बान गांगुली और श्री अवधेश कुमार सिंह ने की है। इस किताब में देश की शिक्षा व्यवस्था और विकल्पों पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों का संकलन है।

इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी जी का मानना था कि भारत में लोगों की नैसर्गिक प्रतिभा और देश की मूल संस्कृति से मेल खाती शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री मुखर्जी का मानना था कि देश की प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा, सभी एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी कोई समझौता किये बगैर शिक्षा की गुणवत्ता को अक्षुण्ण रखते हुए इसे जन सुलभ बनाना चाहते थे, साथ ही वे शिक्षा, व्यापार जगत, देश की जरूरत और रिसर्च के बीच पारस्परिक संबंध की भी पुरजोर वकालत करते थे।

उन्होंने कहा कि श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, केवल 53 वर्ष के अपने जीवन में उन्होंने कई ऐतिहासिक कार्य किये। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में श्री मुखर्जी जी के कई

महत्वपूर्ण भाषणों को प्रकाशित किया गया है, लेकिन मैं उनके द्वारा दिए गए दो भाषणों, एक बंगाल विधानसभा में और दूसरा देश की संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा, जिसने देश में बहुत बड़े अनर्थ को रोका था। उन्होंने कहा कि 1940 में बंगाल विधानसभा में एक बिल पेश किया गया था, जो शिक्षा का इस्लामीकरण करने का प्रस्ताव था जिसको केवल डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दूरदर्शिता के कारण लागू नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि 1951 में केंद्र सरकार विश्व भारती अधिग्रहण बिल लेकर आई थी, उस वक्त भी श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अकेले आवाज बुलंद की थी जिसके कारण ही शिक्षा को देश की संस्कृति के साथ जोड़ने वाले संस्थान बच पाए। ■

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी किताब 'द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड' का विमोचन

'गरीब घर का बालक कर्तव्यपरायणता के कारण प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा'

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवन पर लिखी किताब 'द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड' का 12 जुलाई को दिल्ली में लोकार्पण हुआ। लोकार्पणकर्ता थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहनराव भागवत और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह। यह किताब सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक श्री बिंदेश्वरी पाठक ने लिखी है। इस अवसर पर श्री मोहनराव भागवत ने कहा कि लोगों के बीच जिनका करिश्माई व्यक्तित्व बन जाता है, उनके जीवन चरित्र लिखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व जो दिखता है और जो होता है, उसमें एकरूपता होनी चाहिए। व्यक्तित्व की चमक बाहर से दिखने वाली संपदा से नहीं आती, मन के अंदर की संपदा से आती है। नरेंद्र भाई एक व्यक्ति के नाते, एक स्वयंसेवक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले जैसे थे, वैसे आज भी हैं। प्रसिद्धि की चकाचौंध में रहते हुए भी अपने व्रत को निभाते हुए चलना नरेंद्र भाई को आता है।

इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने बताया कि कैसे एक गरीब घर में जन्मा बालक कर्तव्यपरायणता और ईश्वर-प्रदत्त गुणों के कारण प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तब तक गुजरात की विकास दर 12% रही। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारत को गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मिला है और पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है।

श्री शाह ने कहा कि ईश्वर जो काम करने का मौका देता है, उसे पूरा करना मोदी जी का व्यवहार है। उन्होंने ये साबित किया कि गांव और शहर के विकास में अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की वजह से लोगों को सम्मान के साथ जीने का मौका मिला है। श्री शाह ने कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारत को सही रास्ते पर ले जा सकती है। ■

तीनों देशों की संयुक्त प्रतिबद्धता का प्रदर्शन था 'मालाबार अभ्यास'

बंगाल की खाड़ी/उत्तरी हिंद महासागर में भारत, अमेरिका और जापान की नौ सेनाओं के बीच 'मालाबार अभ्यास' किया गया। मालाबार अभ्यास का यह 21वां संस्करण 10 से 17 जुलाई 2017 के दौरान हुआ। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तीनों नौसेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा के लिए सामान्य समझ और प्रक्रियाओं को विकसित करना था। इस वर्ष समुद्री अभ्यास में एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन, एयर डिफेन्स, एंटी-सबमरीन वारफेयर (एसएसडब्ल्यू), सर्फेस वारफेयर, विजिट बोर्ड सर्च और सीज़र (वीबीएसएस), सर्च एंड रेस्क्यू, संयुक्त मैन्युवर्स और टेक्टिकल प्रोसिजर्स जैसी गतिविधियां संपन्न हुई। इसके अतिरिक्त, 15 जुलाई 2017 को तीनों देशों के अधिकारी समुद्री जहाजों पर सवार हुए।

जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल (जेएमएसडीएफ) की भागीदारी के साथ भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच 1992 में शुरू हुई 'मालाबार अभ्यास' की श्रृंखला से एक बहुआयामी अभ्यास के दायरे और भागीदारी में लगातार वृद्धि हुई है। यह भारत, अमेरिका और जापान के बीच नौसेना सहयोग, तीन लोकतंत्रों के बीच मजबूत और लचीले संबंधों का प्रतीक है।

भारतीय वायुसेना, विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य में अपनी क्षमता के साथ मिसाइल विध्वंसक रणवीर, स्वदेशी तकनीक वाले शिवलिक और सह्याद्री, स्वदेशी एसएसडब्ल्यू कार्वेट कामतोटा, मिसाइल कार्वेट्स कोरा और किरपान, एक सिंधुघोष श्रेणी की पनडुब्बी, टैंकर आईएनएस ज्योति के बेड़े और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान पी8 के साथ इस अभ्यास में भाग लिया।

अमेरिकी नौसेना निमेट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और यूएस 7वें बेड़े के अन्य इकाइयों के जहाजों के साथ इस अभ्यास में भाग लिया। अमेरिकी नौसेना बलों में निमितज़ श्रेणी के विमान वाहक, टिकोनडेरोगा-क्लास क्रूजर प्रिंसटन, एलेली बर्क-क्लास डिस्ट्रॉयर्स किड, हावर्ड और शूप सहित अभिन्न हेलीकाप्टर, एक लॉस एंजिल्स-क्लास की पनडुब्बी और एक लम्बी दूरी का समुद्री टोही विमान पी8 शामिल थे।

मालाबार-17 में 16 जलपोत, दो पनडुब्बियां और 95 से अधिक लड़ाकू विमान भाग लिए। यह अभ्यास भारत, अमेरिका और जापान के बीच आपसी भागीदारी के साथ-साथ आपसी आत्मविश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। दरअसल, यह अभ्यास तीनों देशों की संयुक्त प्रतिबद्धता का एक प्रदर्शन था, जो अभ्यास के जरिए समुद्री चुनौतियों को दूर करने में मदद करेगा और इस अभ्यास से वैश्विक समुद्री समुदाय को भारतीय-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। ■

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना के शानदार परिणाम दिखने लगे हैं: मेनका गांधी

161 बीबीबीपी जिलों में से 104 में जन्म के समय लिंग अनुपात वृद्धि

महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने 28 जुलाई को लोक सभा में कहा कि सरकार का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और इसके उत्साहजनक परिणाम दिखने लगे हैं। श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि बीबीबीपी योजना लॉंच के पहले वर्ष में एक सौ जिलों में शुरू की गई थी और पहले ही साल के अंत तक ही 58 जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात में वृद्धि दिखी। दूसरे वर्ष में योजना 161 जिलों में शुरू की गई, जिसमें से 104 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोत्तरी दिखी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और राजस्थान ने बेहतर परिणाम दिए हैं और उन्हें पुरस्कृत किया गया है। मंत्री ने कहा कि शानदार कार्य के लिए महिला और विकास मंत्रालय ने दस जिलों का अभिनन्दन किया है। इन जिलों में महाराष्ट्र का जलगांव, जम्मू कश्मीर में कठुआ, राजस्थान में झुनझुनू, महाराष्ट्र में ओस्मानाबाद, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, तमिलनाडु में कुड्डालोर, छत्तीसगढ में रायगढ, हरियाणा में यमुनानगर और पंजाब में मनसा शामिल हैं। ■

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री अरुण सिंह
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

रामेश्वरम (तमिलनाडु) में पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा का अनावरण करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, साथ में– केंद्रीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू

गुजरात के सांसदों से बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों से विचार–विमर्श करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

राजस्थान के सांसदों से बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के लिए एक विदाई समारोह की मेजबानी की। गत 23 जुलाई को हैदराबाद हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री मुखर्जी को एक स्मृति–चिन्ह भेंट किया।

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने कमल संदेश के आजीवन सदस्य

कमल संदेश की कैशलेस सदस्यता लें!

आह्वान

आपको जानकर हर्ष होगा कि 6 दिसम्बर 2016 को पार्टी मुख्यालय में भाजपा 'कमल संदेश' का आजीवन सदस्य बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. **श्री अमित शाह** ने पत्रिका की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि 'कमल संदेश' भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय पत्रिका है और यह पाक्षिक रूप में हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है।

हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं 5000/– रुपए का चैक देकर 'कमल संदेश' की आजीवन सदस्यता ली। साथ ही केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर सहित अनेक केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आजीवन सदस्यता ग्रहण की गई है।

'कमल संदेश' हिन्दी एवं अंग्रेजी के दोनों अंकों को 5000/– (पांच हजार रुपये) की सदस्यता शुल्क देकर नियमित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब 'कमल संदेश' के लिए कैशलेस भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध है। कृपया 5000/– (पांच हजार) रुपये का योगदान कर आप भी 'कमल संदेश' (हिन्दी+अंग्रेजी) का आजीवन सदस्य बनें।

एक साल (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹350/-	**तीन साल** (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹1000/-
आजीवन (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹3000/-	**आजीवन** (हिन्दी+अंग्रेजी)	—	₹5000/-

'कमल संदेश' के हमारे पाठकों से अनुरोध है कि इसकी सदस्यता लेकर जीवंत वैचारिक आंदोलन के भागीदार बनें।

कैशलेस बना 'कमल संदेश' सदस्य बनें और बनाएं

☞ **www.kamalsandesh.org, www.bjp.org** पर जाकर कैशलेस भुगतान क्रेडिट/डेबिट/नेटबैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।

☞ साथ ही दिए बार कोड से मोबाइल द्वारा सीधा भुगतान भी कर सकते हैं।

chillr
ACCEPTED HERE
Scan the QR code to make a payment
Click on SCAN & PAY and enter amount
Add this contact to pay
+91 9911026172

"**कमल संदेश**" के नाम से कृपया चेक/ड्राफ्ट निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:
कमल संदेश, पीपी–66, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली– 110003